● वर्ष-4
● अंक-36
रायपुर, गुरुवार
19 सितंबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› क्या आप प्रोफेशनल कोर्स करना...

मोदी का पोस्ट, बोले- समिति की सिफारिशें मंजूर, लोकतंत्र में सहभागिता बढ़ेगी

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को सरकार की मंजूरी

नई दिल्ली। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की दिशा में एक कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसको लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। अपने पोस्ट में मोदी ने लिखा कि कैबिनेट ने एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। मैं इस प्रयास का नेतृत्व करने और हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला से परामर्श करने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद जी को बधाई देता हूं।

प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि यह हमारे लोकतंत्र को और भी अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत परिवर्तनकारी सुधारों का गवाह बन रहा है। आज, इस दिशा में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। नड्डा ने आगे लिखा कि राज्यों में अलग-अलग समय पर चुनाव कराने की मौजूदा प्रणाली विकास प्रयासों में बाधा डालती है और राष्ट्रीय खजाने पर बोझ डालती है। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को अपनाने से सरकार पर चुनाव संबंधी खर्च और वित्तीय बोझ कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने लिखा कि इस ऐतिहासिक निर्णय का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और

संसाधनों के अधिक उत्पादक आवंटन के माध्यम से आर्थिक विकास में तेजी लाने की मोदी जी की दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पहल पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। नड्डा ने आगे लिखा कि राज्यों में अलग-अलग समय पर चुनाव कराने की मौजूदा प्रणाली विकास प्रयासों में बाधा डालती है और राष्ट्रीय खजाने पर बोझ डालती है। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को अपनाने से सरकार पर चुनाव संबंधी खर्च और वित्तीय बोझ कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने लिखा कि इस ऐतिहासिक निर्णय का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारतीय लोकतंत्र ने एक राष्ट्र-एक चुनाव की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत परिवर्तनकारी सुधारों का गवाह बन रहा है। आज, इस दिशा में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के साथ, भारत ऐतिहासिक चुनाव सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। यह स्वच्छ और वित्तीय रूप से कुशल चुनावों के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने और संसाधनों के अधिक उत्पादक आवंटन के माध्यम से आर्थिक विकास में तेजी लाने की मोदी जी की दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को मंजूरी दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज मैं मन से बहुत प्रसन्न हूं, आज कैबिनेट ने पीएम मोदी की अध्यक्षता में बहुत बड़ा

स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में की थी वकालत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की वकालत करते हुए तर्क दिया था कि बार-बार चुनाव देश की प्रगति में बाधाएं पैदा करते हैं। मैं लाल किले से देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के सपने को साकार करने के लिए आगे आएं।

फैसला किया है। हमेशा होने वाले चुनाव देश के प्रगति में बाधक थे इस देश में 24 घंटे चुनाव की तैयारी चलती रहती है....इसलिए विकास के बड़े फैसले नहीं लिए जा पाते। मैं पीएम मोदी को दिल से बधाई देता हूं ऐसा फैसला उनके नेतृत्व में ही हो सकता है। सभी मिलकर इसका समर्थन करें।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि एक समृद्ध लोकतंत्र के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

योगी ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एक देश, एक चुनाव प्रस्ताव को दी गई मंजूरी अभिनंदनीय है।

देश में राजनीतिक स्थिरता, सतत विकास और समृद्ध लोकतंत्र की सुनिश्चितता में यह निर्णय मील का पत्थर सिद्ध होगा। इस युगांतरकारी निर्णय के लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार! उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिखा कि बहुप्रतीक्षित एवं ऐतिहासिक कदम ! नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारतीय लोकतंत्र को और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने की दिशा में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया जाना स्वागत योग्य निर्णय है।

इस फैसले पर क्या बोला विपक्ष

कांग्रेस ने किया विरोध- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसे अव्यावहारिक बताया। उन्होंने एक साथ चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी को चुनाव से पहले एक चुनावी हथकंडा करार देते हुए कहा, जब चुनाव आते हैं, तो वे (भारतीय जनता पार्टी) ये सब बातें कहते हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता भी इसे स्वीकार नहीं करेगी। उनकी यह टिप्पणी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दिये जाने के बाद आयी है।

मायावती ने किया स्वागत- बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया कि देश में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की व्यवस्था के तहत लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज दी गई मंजूरी पर हमारी पार्टी का रुख सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित में होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मल्होत्रा ने कहा कि अगर बीजेपी 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' लागू करना चाहती है तो उसे सभी विपक्षी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों और लोकसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए।

झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यह देश संघीय ढांचे से चलता है। ये फैसले हमें साम्राज्यवाद की ओर धकेल रहे हैं। यह न तो संभव है और न ही व्यावहारिक। यह संविधान पर हमला है। राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि मेरी पार्टी हमेशा कहती है कि इस देश में एक देश एक चुनाव था, 1962 के बाद यह व्यवस्था टूट गई क्योंकि एक दल का प्रभुत्व समाप्त हो गया और कई क्षेत्रीय दलों ने राज्यों में सरकार बना ली। उन्होंने कहा कि अब अगर कोई सरकार गिर जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप राष्ट्रपति शासन लाएंगे?

'एक देश, एक चुनाव' से संघवाद नष्ट हो जाएगा- ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्होंने 'एक देश, एक चुनाव' का लगातार विरोध किया, क्योंकि इससे संघवाद समाप्त हो जाएगा और लोकतंत्र से समझौता होगा। ओवैसी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जारी पोस्ट में कहा कि समय-समय पर चुनाव कराने से लोकतांत्रिक जवाबदेही में सुधार आता है। ओवैसी ने कहा, ''मैंने 'एक देश, एक चुनाव' का लगातार विरोध किया है, क्योंकि यह समाधान नहीं, बल्कि एक समस्या है।

विश्व बांस दिवस

गडकरी ने बेमेतरा में तैयार विश्व के सबसे ऊंचे बैम्बू टॉवर का किया लोकार्पण

बेमेतरा/रायपुर। विश्व बांस दिवस पर आज केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बेमेतरा में तैयार विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टॉवर का ऑनलाइन लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ.रमन सिंह भी लोकार्पण कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। बेमेतरा जिले के ग्राम कठिया में भव्य सृष्टि उद्योग द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे बांस के टॉवर का निर्माण किया गया है। करीब 11 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस टॉवर की ऊंचाई 140 फीट और वजन 7400 किलोग्राम है। पेरिस के एफिल टॉवर जैसी डिजाइन वाला यह टॉवर भव्य सृष्टि उद्योग के फाउंडर और बांस प्रौद्योगिकी से जुड़े गणेश वर्मा ने बनाया है। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बांस-टॉवर का लोकार्पण करते हुए कहा कि भव्य सृष्टि उद्योग बांस पर लगातार अनुसंधान कर इसकी नई-नई खासियतों को सामने ला रहा है। अपनी नई सोच और पहल से उन्होंने 140 फीट ऊंचा यह टॉवर बनाया है। यह टॉवर वजन में हल्का है और इसका जीवन काल कम से कम 25 वर्षों का है। वॉच टॉवर, टेलीकॉम टॉवर, ट्रांसमिशन टॉवर और रेडियो टॉवर के रूप में इसका उपयोग हो सकता है।

उन्होंने कहा कि भव्य सृष्टि उद्योग बांस के उपयोग और इससे निर्मित सामग्रियों की नई-नई डिजाइन और परिकल्पना पर लगातार काम कर रहा है। हम लोग उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। उनके इस कार्य के लिए मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं। गडकरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार यदि बांस के उपयोग के बारे में कोई नीति बनाती है और उसे प्रोत्साहित करती है, तो वहां के आदिवासियों का जीवन बदल जाएगा। छत्तीसगढ़ के हैंडलूम्स, हैंडीक्राॅफ्ट्स और मेटल-क्राॅफ्ट्स में नए डिजाइन बनेंगे तो उनकी अच्छी बिक्री होगी।

प्रमुख समाचार

पंजाब सीएम मान की अचानक बिगड़ी थी तबीयत

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की मंगलवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। सीएम मान की तबीयत उस समय खराब हो गई जब वे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थे। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएम के करीबीयों की मानें तो अब उनका स्वास्थ्य बेहतर है। दिल्ली के सीएम अरविंदर केजरीवाल को जेल से जमानत मिलने पर वह बीते कुछ दिनों से दिल्ली में ही थे। सीएम मान बीते रोज जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे, अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें फौरन चंडीगढ़ सीएम आवास लाया गया। यहां उन्हें ड्रिप लगाई गई। इसके बाद सीएम मान को दोबारा चंडीगढ़ से दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि अब सीएम मान की तबीयत में सुधार है। सीएम मान 13 सितंबर को उस समय दिल्ली गए थे, जब दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद से ही वह दिल्ली में ही रुके हुए थे।

वित्त मंत्री सीतारमण ने की एनपीएस वात्सल्य की शुरुआत

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की, जिससे माता-पिता पेंशन खाते में निवेश करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत कर सकेंगे। माता-पिता ऑनलाइन या बैंक या डाकघर जाकर एनपीएस वात्सल्य में शामिल हो सकते हैं। वात्सल्य खाता खोलने के लिए न्यूनतम योगदान 1,000 रुपये है। इसके बाद सब्सक्राइबर को सालाना 1,000 रुपये का योगदान देना होगा। एनपीएस खातों से निकासी के दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। योजना का शुभारंभ करते हुए सीतारमण ने कहा कि एनपीएस ने बहुत प्रतिस्पर्धी रिटर्न उत्पन्न किया है और लोगों को भविष्य की आय सुनिश्चित करते हुए बचत करने का विकल्प प्रदान करता है। एनपीएस वात्सल्य बच्चों के लिए पहले से मौजूद एनपीएस का ही विस्तार है। पिछले 10 वर्षों में एनपीएस के 1.86 करोड़ ग्राहक हैं और इसकी प्रबंधनाधीन परिसंपत्ति (एयूएम) 13 लाख करोड़ रुपये है।

जम्मू कश्मीर पहले चरण में इंद्रवल सीट पर ज्यादा वोटिंग

जम्मू। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए बुधवार शाम को मतदान खत्म हो गया। पहले दौर में सात जिलों की कुल 24 सीटों के लिए वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक यहां करीब 58 फीसदी मतदान दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा 77.23 फीसदी वोटिंग किश्तवाड़ जिले में तो सबसे कम पुलवामा जिले में 43.87 फीसदी दर्ज की गई। किश्तवाड़ जिले की इंद्रवल सीट पर 80त्न से ज्यादा वोटिंग हुई है। इस चरण में मतदाता 219 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। पहले दौर में जहां मतदान हुआ, उनमें अनंतनाग की सात, पुलवामा की चार, किश्तवाड़, कुलगाम और डोडा की तीन-तीन और रामबन और शोपियां जिले की दो-दो सीटें शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस (गठबंधन), पीडीपी के बीच माना जा रहा है।

21 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं आतिशी

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा के बाद दिल्ली में आतिशी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनने जा रही है। मंगलवार को अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इसके बाद आतिशी ने सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश किया था। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक के दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राष्ट्रपति तथा गृह मंत्रालय को पत्र भेज दिया है। इस पत्र में 21 सितंबर 2024 को आतिशी को सीएम पद की शपथ दिलाने की तिथि प्रस्तावित की गई है। हालांकि, यह सूत्रों की ओर से मिल रही। जानकारी के मुताबिक है अब तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया गया है कि आतिशी किस दिन शपथ लेंगी। केजरीवाल ने रविवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी।उन्होंने तब कहा था कि वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तभी बैठेंगे, जब जनता उन्हें ''ईमानदारी का प्रमाणपत्र'' देगी। आबकारी नीति 'घोटाले' में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे और पिछले सप्ताह जेल से रिहा हुए आप सुप्रीमो ने मंगलवार शाम को उपराज्यपाल सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया।

लाउडस्पीकर ईद पर भी नुकसानदेह, कोर्ट की टिप्पणी

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के जुलूसों के दौरान स्वीकार्य शोर स्तर से ज़्यादा लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर गणेश उत्सव के दौरान स्वीकार्य शोर स्तर से ज़्यादा लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल नुकसानदेह है, तो ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के जुलूसों के दौरान भी इसका वही असर होगा। अदालत ने ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के जुलूसों के दौरान डीजे, डांस और लेजर लाइट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली कई जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाओं में उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह नगर निकायों और पुलिस को ऐसे उच्च-डेसिबल ध्वनि प्रणालियों के उपयोग की अनुमति देने से बचने का निर्देश दे। जनहित याचिकाओं में दावा किया गया है कि न तो कुरान और न ही हदीस (पवित्र पुस्तकें) उत्सव के लिए डीजे सिस्टम और लेजर लाइट के उपयोग को निर्धारित करती हैं। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने गणेश उत्सव से ठीक पहले पिछले महीने पारित एक आदेश का हवाला दिया।

बांग्लादेश का राजनीतिक संकट

आखिर क्यों परदेसी हाथों में खेल रहा है पड़ोसी मुल्क?

राजेश बादल

यह कैसी जम्हूरियत है? एक सरकार थी। चुनाव के ज़रिए चुनी गई थी। उसने अपने मुल्क़ को लोकतान्त्रिक ढंग से चलाने की शपथ भी ली थी। आप निर्वाचन के तरीक़े पर सवाल उठा सकते हैं, चुनाव में धांधली के आरोप लगा सकते हैं और विपक्ष के उत्पीड़न की बात भी कर सकते हैं। इसके बावजूद वहां शेख हसीना वाजेद की ऐसी हुकूमत थी,जो अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की गारंटी देती थी। वह अपनी आज़ादी के आंदोलन में सहायता करने वाले देश से तमाम असहमतियों के बाद भी अच्छे संबंध बना कर रखती थी।

निश्चित ही राष्ट्र के संवैधानिक ढांचे पर उसका नियंत्रण था। लेकिन आज हिन्दुस्तान अपने प्रिय पड़ोसी देश में क्या देख रहा है? वहां हड़बड़ी में सरकार के नाम पर काम चलाऊ व्यवस्था बनाई गई। एक ऐसी सरकार चल रही है,जो संवैधानिक आधार पर नहीं चुनी गई, जिसने बिना चुनाव कराए ही पूर्णकालिक सरकार की तरह बरताव शुरू कर दिया है। इस सरकार में बैठे लोग ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्णय ले रहे हैं, जिनको लागू करना किसी निर्वाचित सरकार के लिए भी आसान नहीं होता। क्या यह नैतिक और संवैधानिक धरातल पर उचित है कि सरकार चला रहा एक झुण्ड बिना जनादेश लिए इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील फ़ैसले ले ? इस घटनाक्रम का क्या अर्थ लगाया जाए? ख़ासतौर पर उन स्थितियों में जबकि सारे फ़ैसले भारत विरोधी हो रहे हों। यहां तक कि जिन आधारों पर देश का गठन हुआ,उन आधारों को ही बदलने का काम शुरू हो गया है। जिस सैनिक शासन ने कभी शेख मुजीब को पाकिस्तान की सत्ता नहीं संभालने दी ,अब वैसा ही सैनिक शासन संविधान बदलने की राह पर चल पड़ा है।बांग्ला पहचान के नाम पर वहां के स्वाधीनता सैनानियों ने पश्चिमी पाकिस्तान से जंग लड़ी,लाखों लोग मारे गए , हज़ारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया और उनकी नृशंस हत्या कर दी गई ,अब उन्ही आततायियों के समर्थन से मुल्क़ में सरकार चल रही है। क्या यह देश भूल गया है कि सारे संसार को मातृभाषा दिवस दिलाने का काम बांग्लादेश के छात्रों ने किया था।

कहानी यह थी कि पाकिस्तान के हुक्मरान बांग्ला भाषा को हिन्दू संस्कृति से जोड़कर देखते थे। इस कारण वे पूर्वी पाकिस्तान से बांग्ला भाषा का नामोनिशान मिटा देना चाहते थे और उर्दू थोपना चाहते थे। लेकिन वहां के लोग बांग्ला संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहते थे। विरोध में ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने 21 फरवरी 1952 को बांग्ला भाषा के समर्थन में प्रदर्शन किया। उन पर पाकिस्तानी सेना ने गोलियां बरसाईं। इसमें सोलह छात्र मारे गए थे। इसके बाद यूनेस्को ने 1999 में मातृभाषा के लिए क़ुर्बानी देने वाले छात्रों की याद में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का ऐलान किया था।

इधर, अब उसी बांग्ला भाषा को हटाने पर काम चल रहा है। यानी अब वही हो रहा है ,जो पाकिस्तानी फ़ौजी सत्ता 1952 में चाहती थी। विडंबना है कि वे अब अपने राष्ट्रगान को भी बदलना चाहते हैं, क्योंकि वह एक भारतीय गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था।ज़ाहिर है सत्ता पलटने की यह साज़िश शेख हसीना के विरुद्ध नहीं ,बल्कि भारत के विरुद्ध थी।

तनिक अंतरराष्ट्रीय अतीत को टटोलें तो स्पष्ट हो जाता है कि भारत के विभाजन के बाद से ही पाकिस्तान पर अमेरिका का वरदहस्त रहा है। उसने पाकिस्तान को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया। इसी तरह इस मुल्क़ पर चीन ने अपना प्रभाव बनाकर रखा। उन दिनों शीत युद्ध की स्थिति में अमेरिका बनाम सोवियत संघ की स्थिति बनी हुई थी। जब सोवियत संघ का विखंडन हो गया और धीरे-धीरे चीन महाशक्ति के रूप में उभरा तो फिर यह अमेरिका बनाम चीन हो गया। हालांकि सोवियत संघ के विखंडन के बाद रूस की ताक़त भी कम नहीं थी,इसलिए अमेरिका बीते तीन दशक से गंभीर प्रयास कर रहा है कि रूस और चीन पर नज़र रखने के लिए अपना सैनिक अड्डा भारतीय उप महाद्वीप में क़ायम करे। इसके लिए उसने सबसे पहले पाकिस्तान को चुना, किन्तु चीन के असर से पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सका।

यह प्रस्ताव उसने इमरान ख़ान के प्रधानमंत्री रहते किया था मगर इमरान ने भी मना कर दिया।आपको याद होगा कि सत्ता से हटाए जाने के बाद ही इमरान ख़ान ने बयान दिया था कि उनकी सरकार अमेरिका के इशारे पर गिराई गई है। उन्हें जेल में डालने का काम भी अमेरिका के इशारे पर हुआ है।

यह बात छिपी नहीं है। उसने तो भारत पर डोरे डाले थे । यूपीए सरकार के दरम्यान हुआ परमाणु समझौता इस दिशा में भारत को ललचाने वाला क़दम माना जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र की मज़बूती के चलते यहाँ भी उसकी दाल नहीं गली। इसके बाद उसने नेपाल का रुख किया।ज़ाहिर है कि भारत और चीन -दोनों ही इसके पक्ष में नहीं थे। इसलिए नेपाल से भी अमेरिका को निराशा लगी।

इसके बाद ले देकर बांग्लादेश बचता था।अमेरिका ने शेख हसीना से सेंट मार्टिन द्वीप मांगा था पर,शेख हसीना ने इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी सरकार गिरने के बाद कहा था- मैं सत्ता में बनी रह सकती थी,अगर मैंने सेंट मार्टिन की संप्रभुता को छोड़ दिया होता और अमेरिका को बंगाल की खाड़ी में अपना रुतबा क़ायम करने दिया होता।

आपको याद दिला दूं कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था तो भारत की घेराबंदी करने के लिए फौजी तानाशाह जनरल अयूब ख़ान ने इस द्वीप को अपने शासनकाल में अमेरिका को पट्टे पर दे दिया था। जब बांग्लादेश बना तो पट्टा समाप्त कर दिया गया। शेख़ हसीना के लिए वह मुश्किल घड़ी थी ,जब अमेरिका ने यह द्वीप फिर पट्टे पर मांग लिया था।

अधीक्षिका को रोकने छात्राओं ने मुख्य द्वार पर जड़ा ताला

जगदलपुर। बस्तर जिले के बास्तानार ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले कन्या आश्रम बाग मुंडी पनेड़ा के बच्चों के आंसुओं की झड़ी उस समय शुरू हो गई, जब वहां की अधीक्षिका ने इस्तीफा दे दिया, अधीक्षिका को जाने से पहले कन्या आश्रम की छात्राओं ने गेट में ताला लगा दिया, 4 दिन के बाद आखिर अधीक्षिका ने अपना सामान लेकर वहां से चली गई।

बताया जा रहा है बास्तानार ब्लाक के 100 सीटर कन्या आश्रम बागमुंडी पनेड़ा में 2020 में अधीक्षिका के रूप सुखमती मौर्य ने पदभार लिया था, इन 4 सालों में सुखमती मौर्य से बच्चों को इस कदर लगाव हो गया कि बच्चों ने उसे अपना परिवार का हिस्सा बना लिया था, अपना हर दुख सुख में अपना समझ हर बातों से लेकर बात करते थे, लेकिन अचानक 4 सालों के बाद अधीक्षिका ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अधीक्षिका के द्वारा इस्तीफा दिए जाने का पता चलते ही छात्राओं के द्वारा रोना शुरू हो गया, 4 दिनों तक छात्राओं ने आश्रम के मुख्य द्वार में ताला लगाकर उसे जाने से रोक दिए, बच्चों का अधीक्षिका के प्रति प्रेम इस कदर बढ़ा हुआ था कि छात्राओं का रो रोकर बुरा हाल हो गया था, आंसू थमने का नाम नही ले रहा था, कोई अधीक्षिका के पैर पकड़ उसे जाने से रोक रहा था तो कोई उसे गले लगाकर अपने प्यार का इजहार कर रहा था, कोई भी नही जान पाया कि आखिर अधीक्षिका के द्वारा इस्तीफा क्यों दिया गया। लेकिन बच्चों के इस प्यार को वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ, जिसके बाद इस आश्रम में एक नई अधीक्षिका की नियुक्ति भी कर दिया गया है, लेकिन उसने अब तक यहां पर आकर कोई भी चार्ज नहीं लिया है।

पढ़ाई छोड़कर कलेक्ट्रेट पहुंचे स्कूली बच्चे, स्कूल के दो शिक्षकों का दूसरी जगह किया गया संलग्नीकरण

कबीरधाम। कबीरधाम जिले के ग्राम कुसुमघटा स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के करीब 50 से अधिक स्कूली बच्चे अचानक अपनी पढ़ाई छोड़कर आज बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए थे। इस स्कूल के दो शिक्षकों का किसी दूसरे स्कूल में संलग्नीकरण किया गया है। इसी से स्कूली बच्चे नाराज है।

कलेक्ट्रेट पहुंचे स्कूली बच्चे दामिनी चन्द्रवंशी, सजना चन्द्रवंशी, राजेश्वरी, जिज्ञासा, नुरेशा ने बताया कि उनके स्कूल के शिक्षक तुलसी राम तांडिया व महेश्वर प्रसाद द्विवेदी का दूसरे स्कूल में संलग्नीकरण किया गया है।

इन दोनों शिक्षकों के दूसरे स्कूल में चले जाने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आने वाले समय में परीक्षा शुरू होगी। इस बीच संलग्नीकरण किया जाना गलत है। बच्चों ने बताया कि एक दिन पहले 17 सितंबर को जिला शिक्षा अधिकारी के पास ज्ञापन दिया गया था। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में दूसरे दिन आज 18 सितंबर बुधवार को कलेक्टर के पास आवेदन देकर दोनों शिक्षकों को फिर से हमारे स्कूल में पदस्थ करने की मांग किया गया है।

आंगनबाड़ी में चल रहा वजन त्योहार वजन मापने पहुंचे कलेक्टर

बालोद। आंगनबाड़ी केन्द्रों में इन दोनों वजन त्यौहार मनाया जा रहा है ताकि बच्चों को सुपोषण मिल पाए उनके लिए बेहतर सुपोषण व्यवस्था किया जाए और इसी बीच बच्चों का वजन मापने के लिए बालोद कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवल स्वयं बच्चों के बीच पहुंच गए उन्होंने बालोद ब्लाक के ग्राम उमरादाह आंगनवाड़ी क्रमांक एक पहुंचकर बच्चों का वजन और ऊंचाई माप और उनके खान-पान संबंधित जानकारी भी ली इस दौरान पता चला कि जिस आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचे हुए हैं वहां सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे थे इसको लेकर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए और गर्म भोजन जो महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से चलाया जा रहा है उसके संबंध में जानकारी ली।

कलेक्टर ने बताया कि बच्चों के लिए जो पोषण ट्रैकर एप बनाया गया है उसके माध्यम से भी कार्यों की जानकारी यहां पर ली गई है वहीं कार्यकर्ता ने बताया कि जो कुपोषित बच्चे थे वो सामान्य की श्रेणी में आ रहे हैं और शासन द्वारा तय मेनू के हिसाब से बच्चों को प्रतिदिन भोजन दिया जा रहा है वहीं उन्होंने बताया कि इस आंगनबाड़ी में कुल दर्ज संख्या 34 है और 17 बच्चे कुपोषण की श्रेणी में हैं जिसमे से 3 बच्चे अति कुपोषित हैं।

कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने कहा कि यहां पर हम सबका लक्ष्य है कि बच्चों को सुपोषण से जोड़ना है बच्चे स्वस्थ्य रहेंगे तो राज्य और देश स्वास्थ्य रहेगा आपको बता दें कि कलेक्टर के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी भी दौर में आंगनबाड़ियों के निरीक्षण को लेकर पहुंचे हुए थे आंगनबाड़ी केदो में पहुंचकर कलेक्टर ने अपने सामने ही बच्चों का वजन करवाया और ऊंचाई भी नवी इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि बच्चों के लिए जो भी सुपोषण आहार संभव है उन्हें दिया जाए वहीं गर्म भोजन के स्थितियों में भी सुधार लाया जाए उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं कि और क्या बेहतर किया जा सकता है।

स्व रोजगार से जोड़ने स्व सहायता समूह की महिलाओं को दिया जाएगा ड्रोन प्रशिक्षण

बलौदाबाजार। नमो ड्रोन दीदी योजना अंतर्गत बलौदाबाजार जिले के स्व सहायता समूह की अधिक से अधिक महिलाओं को ड्रोन उडाने क़ा प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने कृषि विभाग के अधिकारियों को इस सबंध में जरुरी निर्देश दिए हैं। ड्रोन दीदी श्रीमती निरुपा साहू एवं ड्रोन पायलट निखिल कन्नौजे ने कलेक्टर श्री सोनी से मुलाकात कर अपने अनुभव साझा किये। कलेक्टर ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें प्रेरणा स्रोत बताया।उन्होंने उर्वरक व कीटनाशक छिड़काव में ड्रोन के उपयोग को किसानों के लिए फायदेमंद कहा और ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की बात कही।

विकासखंड बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम लाहौद निवासी ड्रोन दीदी श्रीमती निरुपा साहू ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्होंने ड्रोन से दवाई छिड़काव क़ा कार्य अप्रैल 2024 से शुरू किया है। इसके पूर्व उन्होंने ग्वालियर स्थित प्रशिक्षण संस्थान से ड्रोन उडाने का 15 दिन का प्रशिक्षण लिया। उन्होने बताया कि बिहान अंतर्गत वैभव लक्ष्मी स्व सहायता समूह से जुडी हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में जानकारी कृषि विभाग के अधिकारियो से मिली। ड्रोन दीदी ने बताया कि ड्रोन से यूरिया या कीटनाशक छिड़काव के लिए प्रति एकड 300 रुपये शुल्क लेती हैं और उन्हें अब तक करीब 25 हजार रूपये की आय हो चुकी है। ग्राम लटुआ निवासी ड्रोन पायलट निखिल कन्नौजे ने बताया कि वह इफ्को कंपनी से जुडा है और कंपनी के माध्यम से ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण लिया है। उन्होंने बताया कि ड्रोन को 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तक उड़ाया जा सकता है। विगत अप्रैल माह से करीब 88 एकड़ खेतों में दवाई का छिड़काव ड्रोन से कर चुके हैं। ज्ञातव्य है कि केंद्र सरकार द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि आने वाले चार वर्षों में 15 हजार स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराया जाए। यह ड्रोन, महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में उर्वरकों का छिड़काव करने के लिए किया जाएगा।

लोहारीडीह हत्याकांड मामले में नया मोड़, एक आरोपी की जेल में संदिग्ध मौत

कबीरधाम। कबीरधाम जिले के जंगल रेंगाखार थाना क्षेत्र के ग्राम लोहारीडीह में बीते रविवार को हुए हत्याकांड व आगजनी के बाद अब नया मोड़ आ गया है। आज बुधवार को हत्याकांड व आगजनी के एक आरोपी की जेल में संदिग्ध मौत हो गई है। इस आरोपी को कवर्धा के जिला जेल में रखा गया था। बताया जा रहा है कि आरोपी की सुबह तबीयत बिगड़ने के बाद जिला अस्पताल लाया गया। अस्पताल में आने से पहले इसकी मौत हो गई थी।

मृतक का नाम प्रशांत साहू उम्र 27 निवासी ग्राम लोहारीडीह है। मृतक का जिला अस्पताल में पीएम कराया जाएगा। ऐसे में परिजनों को अस्पताल बुलाया जा रहा है। परिजनों की उपस्थिति में पंचनामा कर पीएम होगा। दूसरी ओर आरोपी की मौत के बाद पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के बाद जेल भेजा गया था। बता दे कि लोहारीडीह मामले में अब तक 69 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से 36 पुरुष व 33 महिला है। इस घटना के बाद पुलिस ने कुल 5 अलग-अलग एफआईआर दर्ज किया है।

ये था पूरा मामला

बीते रविवार को इस गांव से 5 किमी दूर एमपी-सीजी बॉर्डर पर गांव के शिव प्रसाद साहू उर्फ कचरू साहू का शव फांसी पर लटके मिला। इसकी हत्या की शक को लेकर ग्रामीणों ने गांव के ही रघुनाथ साहू के घर हमला कर दिया। घर को आग के हवाले कर दिया है। कबीरधाम एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव अपनी टीम के साथ गांव में पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में एसपी समेत 10 पुलिसकर्मी घायल हुए।

देर शाम पुलिस की टीम गांव के भीतर आग लगे हुए घर पर पहुंची, जहां पर रघुनाथ साहू का शव जला हुआ मिला। इस गांव में भूमि विवाद चल रहा था। रघुनाथ साहू के परिवार व ग्रामीणों के बीच काफी दिनों से विवाद चला आ रहा था। अब यह विवाद रौद्र रूप ले लिया। जिस युवक की शव जंगल में मिली है, वह एमपी के बालाघाट जिले में आता है। ऐसे में बालाघाट पुलिस मामले की जांच कर रहीं है। गांव में आगजनी व हत्या की जांच कबीरधाम पुलिस कर रहीं है। वर्तमान में गांव में पुलिस व प्रशासन की टीम मौजूद है।

लोहारीडीह आगजनी और हत्याकांड मामला

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने गांव का किया दौरा, भाजपा सरकार को घेरा

कबीरधाम। बीते रविवार को कबीरधाम जिले के नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्र जंगल रेंगाखार के ग्राम लोहारीडीह में हुए आगजनी व हत्याकांड के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांव का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों व पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पूर्व में विवाद होने के बाद भी शासन-प्रशासन लापरवाह रहा है। यह घटना पूरी तरह से इस भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन की नाकामी है। पूर्व सीएम ने कहा कि लोहारीडीह की यह घटना बेहद दुर्भाग्यजनक है और साफ तौर पर पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। पुलिस चाहती तो इस घटना को रोक सकती थी, लेकिन वो वीडियो बनाने में मस्त रही और अब बेगुनाहों को पकड़ कर मारपीट कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है शिवप्रकाश साहू की मौत की जांच हो और पुलिस लोगों को प्रताड़ित करना बंद करे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और ग्रामीणों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील की।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्जिंग से लगी आग, तीन लोग फंसे

दुर्ग। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक मकान में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने से वहां काम करने वाले तीन लोग अंदर ही फंस गए। आग की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। जहां सबसे पहले चौथे मंजिल पर फंसे तीन लोगों का रेस्क्यू किया और उसके बाद आग पर काबू पाया। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना प्रभारी विजय यादव ने बताया कि गवली पारा में देर रात आग लगाने की सूचना मिली थी जहां उपयुक्त मकान में सोने चांदी की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। जिस फैक्ट्री में आग लगी। जहां सबसे ऊपर मंजिल पर कारीगर रहते थे जो इस आग की वजह से ऊपर फंसे हुए थे जिन्हे पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने छत तोड़कर बाहर सुरक्षित निकला गया। इसके बाद दमकल की टीम आग बुझाने में जुट गई। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आग लगाने का कारण ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्जिंग पर लगाया हुआ था अचानक शार्ट सर्किट हुआ और स्कूटर में आग लग गई।

दंतेवाड़ा में फिर मासूम का अपहरण, महीने में दूसरी घटना

दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में एक और मासूम बच्चे का अपहरण हो गया। महीनेभर में अपहरण का यह दूसरा मामला है। इस घटना से लोग दहशत में है। बच्चा महज 18 दिन का था। मां अपने दूधमुंहे बच्चे को घर में लेटाकर पानी लेनी गई, तभी बच्चा चोरी हो गया। यह घटना बचेली थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। इस मामले में एएसपी आरके बर्मन ने कहा, संदेहियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर गहनता से पूछताछ कर रहे। बता दें कि एक सितंबर को भी दंतेवाड़ा जिले के पोंदुम गांव में 6 माह के बच्चे का अपहरण हुआ था। इस मामले में अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। इस घटना के बाद आदिवासी समाज में आक्रोश है। लोगों ने हाल ही में दंतेवाड़ा बंद कराकर आरोपियों को जल्द पकड़ने की आवाज भी उठाई थी। फिर भी पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई तत्परता नहीं दिखाई है।

छत्तीसगढ़ में पहाड़ी पर नजर आया तेंदुओं का झुंड

कांकेर। कांकेर के डूमाली गांव की पहाड़ी पर एक साथ पांच तेंदुए नजर आने से इलाके में दहशत का माहौल है। यह घटना कांकेर शहर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर हुई, जहां ग्रामीणों ने तेंदुओं को देखा और तुरंत वन विभाग को सूचित किया। इन तेंदुओं में तीन शावक और 2 व्यस्क शामिल हैं, तेंदुओं का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि यह पहली बार है जब कांकेर में इतनी बड़ी संख्या में तेंदुए एक साथ दिखाई दिए हैं। कांकेर के पहाड़ी इलाके तेंदुओं के बसेरे के रूप में जाने जाते हैं। इससे पहले भी यहां तेंदुओं द्वारा लोगों और मवेशियों पर हमला किए जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे स्थानीय लोगों में पहले से ही भय बना हुआ है। वन विभाग की टीम ने लोगों से जंगल की ओर न जाने की अपील की है।

सालभर में एक बार खुलने वाला मां लिंगेश्वरी मंदिर

कोण्डागाँव। अपनी अद्भुत प्राकृतिक छटाओं एवं अनूठी आदिम संस्कृति के लिए प्रसिद्ध बस्तर की वादियों में एक ऐसी प्राकृतिक गुफा है, जिसका द्वार साल में केवल एक बार खुलता है। इस साल 18 सितंबर को विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद माता लिंगेश्वरी गुफा मंदिर का द्वार श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोला गया। श्रद्धालु इस द्वार के खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कोण्डागाँव जिले के फरसगांव से बड़ेडोंगर मार्ग पर स्थित ग्राम आलोर से तीन किलोमीटर दूर ग्राम झाटीबन की पहाड़ियों में एक ऐसी गुफा हैं, जहां माता लिंगेश्वरी विराजमान हैं। इस गुफा मंदिर का द्वार साल में एक बार एक ही दिन के लिए बुधवार को खोला गया। लिंगेश्वरी माता के मंदिर का द्वार खोलने की तैयारी सुबह करीब 4 बजे समिति के सदस्य, ग्राम प्रमुख व पुजारी ने की। पूरे रीति-रिवाज से पूजा-अर्चना करने बाद गुफा मंदिर के मुख्यद्वार पर रखे पत्थरों को हटा कर खोला गया। गुफा मंदिर का द्वार खोलने के बाद हजारों की संख्या में आए श्रद्धालुओं को गुफा के बाहर से माता के दर्शन करने दिया गया।

कैंप में जवान ने अपने साथियों पर चलाई गोली

बलरामपुर रामानुजगंज। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पुलिस कैंप में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के एक जवान ने अपने साथियों पर गोली चला दी। गोलीबारी में दो जवानों की मौत हो गई है, जबकि दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को आनन-फानन में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की पुष्टि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने की है। मिली जानकारी के मुताबित घटना सामरी थाना के पुंदाग पुलिस कैंप की है, बलरामपुर के भूताही पुलिस कैंप में सीएएफ के आरक्षक ने अपने साथियों पर राइफल से फायरिंग कर दी। घटना में एक आरक्षक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य जवान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं दो अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हैं जिनका उपचार जारी है। एसपी ने बताया कि आरक्षकों के बीच कोई विवाद नहीं हुआ था और गोली चलाने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच मं जुटी है।

महासमुंद में दंतैल हाथी का उत्पात, एक दर्जन से ज्यादा गांवों में अलर्ट

महासमुंद। महासमुंद में दंतैल हाथी पिछले कुछ दिनों से उत्पात मचा रहा है। दंतैल हाथी ने राइस मिल में उत्पात मचाने के बाद गांव की ओर रुख किया।जिसके बाद हाथी मित्रों ने हाथी को वापस जंगल की ओर खदेड़ा। आपको बता दें कि गरियाबंद से निकला एमई-3 नामक दंतैल हाथी महासमुंद वनपरिक्षेत्र के ग्राम कोना पहुंच गया है। जहां बीती रात हाथी गुरु तेग बहादुर राइस मिल में घुस गया। जिसे हाथी मित्र दल की तत्परता से वहां से खदेड़ा गया।

ग्रामीणों को हाथी देखे जाने पर तुरंत वन विभाग को सूचित करने की अपील की गई है, ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें।वही पूरे मामले पर महासमुंद वन परिक्षेत्र के वन

परिक्षेत्राधिकारी सियाराम कर्मकार ने फोन के माध्यम से बताया कि इस दंतैल हाथी का नाम एमई-3 है और यह गरियाबंद जिले से भटककर बीती रात हमारे महासमुंद वन परिक्षेत्र के कोना गांव पहुंच गया है।

परिक्षेत्राधिकारी सियाराम कर्मकार ने कहा हाथी कक्ष क्रमांक 64 के फेसिंग तारों को तोड़ते हुए कक्ष क्रमांक 59, 60, 61, 62, 63 वन विकास निगम 859 की ओर चला गया है।वर्तमान में हाथी गौरखेड़ा के जंगलों में विचरण कर रहा है।जहां हमारी टीम लगातार हाथी पर नजर जमाए हुए है। दर्जनों गांवों को भी अलर्ट किया गया है।

इसके बाद हाथी ने महासमुंद-बागबाहरा हाइवे पार कर कक्ष क्रमांक 64, गौरखेडा के जंगल में विचरण कर रहा है।हाथी के इलाके में पहुंचने से ग्रामीणों में डर का माहौल भी काफी देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले इसी एमई-3 हाथी ने कोसरंगी गांव में एक व्यक्ति को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था। वन विभाग ने एहतियात के तौर पर एक दर्जन गांवों सिरगिड़ी, उमरदा, गौरखेडा, अरंड, मुडमार, सोरिद, बनसिवनी, लोहारडीह, घोघीबाहरा, बंजारी, कोडार में अलर्ट जारी किया है।

मनरेगा के माध्यम से हुआ पीपरबहरा में शिक्षा में सुधार

■ इंटरलॉकिंग सड़क बनने से शिक्षा में आया सुधार

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) ने क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। इस योजना का उद्देश्य न केवल गरीब ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करना है, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाना है। ऐसी ही एक कहानी है छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के ग्राम पंचायत पीपरबहरा की जहाँ मनरेगा के माध्यम से इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण का कार्य किया गया और इसका सीधा लाभ विद्यालय के बच्चों और शिक्षकों को मिला।

ग्राम पंचायत पीपरबहरा, एक ऐसा गाँव है जहाँ वर्षों से विद्यालय और आंगनबाड़ी तक जाने का मार्ग बेहद कठिन था। मुख्य मार्ग से मझपारा आंगनबाड़ी और प्राथमिक शाला तक का रास्ता

कच्चा था, जिससे बारिश के दिनों में बच्चों और शिक्षकों के लिए आना-जाना बेहद मुश्किल हो जाता था। खासकर बरसात के दिनों में स्थिति इतनी खराब हो जाती थी कि कीचड़ और पानी भरने की वजह से स्कूल की गतिविधियाँ प्रभावित होती थीं। आखिरकार मनरेगा के तहत इस समस्या का समाधान किया गया। शासन द्वारा मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत पीपरबहरा को सड़क निर्माण हेतु कुल स्वीकृत राशि 8 लाख 69 हजार 571 रुपए की मंजूरी प्राप्त हुई थी, जिससे ग्राम पंचायत पीपरबहरा में इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मझपारा आंगनबाड़ी और प्राथमिक शाला तक एक सुरक्षित और सुविधाजनक मार्ग प्रदान करना था। कार्य शुरू होते ही गाँव के लोगों और विशेष रूप से बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। सड़क का निर्माण तेजी से हुआ और कुछ ही महीनों में यह सड़क बनकर तैयार हो गई। अब बच्चों और शिक्षकों के लिए यह सड़क न केवल आसान पहुँच प्रदान करती है, बल्कि उनके दैनिक जीवन में भी कई सकारात्मक बदलाव लेकर आई है। पहले जहाँ बरसात के दिनों में कीचड़ और पानी भरने की समस्या थी, अब वहाँ एक साफ और सुंदर मार्ग है, जिससे विद्यालय तक पहुँचना बहुत आसान हो गया है। इस सड़क निर्माण का सबसे बड़ा प्रभाव गाँव के शिक्षा स्तर पर पड़ा है। जहाँ पहले बच्चों का स्कूल आना-जाना असुविधाजनक होने के कारण उनकी उपस्थिति कम होती थी, अब बच्चों की उपस्थिति में स्पष्ट सुधार देखा गया है। उनके चेहरे पर पढ़ाई के प्रति उत्साह साफ दिखाई देने लगा है।

संक्षिप्त समाचार

आरएसएस समन्वय बैठक में शामिल होने प्रदेश अध्यक्ष के साथ पहुंचे उप मुख्यमंत्री

रायपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि बहुत आगे की सोचकर बैठक हो रही है। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बहुत से कार्य विभाजन हुए हैं, सामाजिक कार्यों का विभाजन हुआ है, इन सब पर चर्चा होगी। इसके अलावा आगे के कार्यों की तैयारियों पर भी बात होगी। रोहिणीपुरम शिक्षण संस्थान में आयोजित आरएसएस की समन्वय बैठक में शामिल होने पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा में निगम मंडल की नियुक्ति पर कहा कि निगम मंडल बाद का विषय है। पहले प्राधिकरण पर सीएम चिंता कर रहे हैं। जल्द इस पर निर्णय होगा। वहीं नवरात्र के पहले जारी होने के सवाल पर कहा कि नवरात्र तो अभी दूर है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव के अलावा वित्त मंत्री ओपी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा में शामिल होने पहुंचे हैं। आरएसएस के प्रमुख पदाधिकारी के साथ हो रही बैठक में निकाय चुनाव, सदस्यता अभियान, सेवा पखवाड़ा समेत अन्य विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा।

रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने गठित की चुनाव संचालन समिति

रायपुर। रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा उप-चुनाव के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने चुनाव संचालन समिति का गठन किया है। समिति में पूर्व मंत्री एवं पूर्व कार्यकारी पीसीसी अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, पूर्व मंत्री एवं पूर्व पीसीसी अध्यक्ष धनेन्द्र साहू, पूर्व मंत्री रविन्द्र चौबे, पूर्व मंत्री एवं पूर्व पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, पूर्व मंत्री एवं पूर्व पीसीसी कार्यकारी अध्यक्ष डॉ। शिवकुमार डहरिया, पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, प्रदेश प्रतिनिधि रुचिर गर्ग, रायपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष उधो राम वर्मा को शामिल किया गया है।

सह-प्रभारियों को जिले और विधानसभावार सौंपा गया प्रभार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरी निकाय चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस ने सह प्रभारियों एसए सम्पत कुमार, जरिता लैतफलांग और विजय जांगिड़ को जिला और विधानसभावार जिम्मेदारी सौंप दी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने यह जिम्मेदारी सौंपी है। इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। आदेशानुसार, तीनों प्रभारियों को अपने-अपने जिले और विधानसभावार क्षेत्रों में सक्रिय होने के निर्देश दिए गए हैं। अपने क्षत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर क्षेत्र की फीडबैक लेकर संगठन को सौंपे। इसमें सह प्रभारियों एसए सम्पत को 31, जरिता लैतफलांग को 28 और विजय जांगिड़ को 31 विधानसभा क्षेत्रों का प्रभार दिया गया है।

दीक्षांत समारोह में 1515 छात्र-छात्राएं होंगी सम्मानित

रायपुर। रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में 1515 छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। जिनमें 18 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक, 55 विद्यार्थियों को पीएचडी, 1440 विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर उपाधि प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा प्रशांत द्विवेदी और डा। सुरेंद्र दुबे को मानद उपाधि दिया जाएगा। उक्त जानकारी विवि के कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह ने बताया कि यह उपाधि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका के हाथों दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी की आधारशिला शिक्षा देने के उद्देश्य से रखी गई है ताकि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के लिए शिक्षा, संस्कार, चरित्र निर्माण एवं रोजगार का मार्ग प्रशस्त कर सकें।

आज शाम 4 बजे से बंद हो जाएंगी शराब दुकानें

रायपुर। गणेश विसर्जन के अवसर पर कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रायपुर और बिरगांव नगर निगम क्षेत्रों में 19 सितंबर को शाम 4 बजे के बाद सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के तहत आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, समस्त देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के साथ रेस्टोरेंट बार, होटल बार, क्लब आदि स्थानों पर भी शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। कलेक्टर ने सभी से आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

किसानों को 8।92 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित

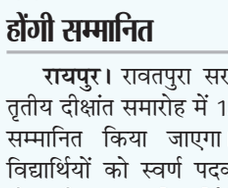

रायपुर। प्रदेश के किसानों को चालू खरीफ सीजन में विभिन्न फसलों की बोनी के लिए सहकारी समितियों एवं निजी क्षेत्र के माध्यम से सुगमता के साथ प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तक किसानों को विभिन्न खरीफ फसलों के 8 लाख 92 हजार क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण किए गए हैं, जो कि राज्य में बीज की मांग का 91 प्रतिशत है। गौरतलब है कि राज्य में खरीफ की विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज की कुल मांग 9 लाख 78 हजार क्विंटल है, इसके विरूद्ध 9 लाख 31 हजार क्विंटल प्रमाणित बीज भण्डारण किया जा चुका है। किसानों को अब तक 8।92 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण किया गया है, जो मांग का 91 प्रतिशत है।

वन नेशन वन इलेक्शन से देश के विकास में आएगी तेजी

रायपुर। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस मामले में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, इससे देश का विकास तेजी से होगा। देश में एक साथ चुनाव हो सकेंगे। आचार संहिता के कारण विकास के कार्य रुकते हैं। कांग्रेस पिछले 77 सालों में देश का विकास नहीं चाहती थी। एक देश एक चुनाव का मसला लंबे समय से टलता रहा है। मोदी जी का यह निर्णय स्वागत योग्य है।

बता दें कि बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन बिल के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। खबर ये है कि सरकार शीतकालीन सत्र में इस पर एक बिल ला सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आए हैं। पीएम मोदी ने कहा था, 'मैं सभी से एक राष्ट्र एक चुनाव के संकल्प को हासिल करने के लिए एक साथ आने का अनुरोध करता हूं, जो समय की मांग है। पीएम मोदी ने कहा था, 'मैं सभी से एक राष्ट्र एक चुनाव के संकल्प को हासिल करने के लिए एक साथ आने का अनुरोध करता हूं, जो समय की मांग है।' लोकसभा चुनाव से पहले आजतक से विशेष बातचीत में पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर कहा था कि सरकारों के पूरे पांच साल के कार्यकाल के दौरान चुनाव ही नहीं होते रहने चाहिए। उन्होंने कहा था, 'मैं हमेशा कहता हूं कि चुनाव सिर्फ तीन या चार महीने के लिए होने चाहिए। पूरे पांच साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। इससे चुनावों का प्रबंधन करने वाले खर्च में कटौती होगी।

वर्तमान समय और संविधान के हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन संभव ही नहीं : सिंहदेव

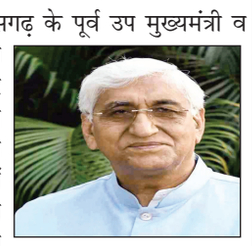

रायपुर। वन नेशन वन इलेक्शन पर छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता टीएस सिंह देव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आज के समय और संविधान के अंतर्गत यह संभव नहीं है। मान लीजिए जनवरी 2025 से वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया है। अब पूरे देश की विधानसभाओं और लोकसभा के एक साथ चुनाव होंगे। किसी राज्य या केंद्र की सरकार दो साल बाद गिर जाती है और यह सरकार पांच साल तक के लिए चुनी जाती है, यानि उसका अगला चुनाव 2032 (जहां की सरकार गिरी हो) में आएगा और बाकी जगहों पर चुनाव 2030 में होंगे। इस स्थिति में वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा? यह संभव ही नहीं है।

सिंहदेव ने कहा, संविधान के उन प्रावधान का क्या होगा, जिसमें कहा गया है कि ऐसी खाली जगहें जो 6 महीने तक खाली रही है, वहां पर चुनाव कराना अनिवार्य है। इस प्रावधान में भी फिर संशोधन करना पड़ेगा।

स्टार्टअप्स से ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले : रमेन डेका

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय दुर्ग अंतर्गत गठित ग्रामीण प्रौद्योगिक और उद्यमिता फाउंडेशन के तहत किये जा रहे स्टार्टअप्स का प्रस्तुतीकरण देखा। उन्होंने सभी स्टार्टअप्स की सराहना करते हुए इसे आम व्यक्ति के लिए सरल व सुलभ बनाने पर बल दिया। राज्यपाल श्री डेका ने सभी उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न योजनाओं को प्रोत्साहित किया और कहा कि स्टार्टअप्स के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार से जोड़ सके ऐसी योजनाएं बनाई जायें। इस संबंध में उन्होंने उद्यमियों का मार्गदर्शन किया और उपयोगी सुझाव दिये। राजभवन के कांफ्रेंस हॉल में आज उद्यमियों ने 6 स्टार्टअप्स योजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया। सुश्री विनिता पटेल ने ग्रामीण महिलाओं विशेषकर आदिवासी समुदाय की महिलाओं को ध्यान में रखते हुए पुनः उपयोग में आ सकने वाले सेनेटरी पैड निर्माण की योजना बताई। श्री करण चंद्राकर ने केले पौधे के अपशिष्ट से कपड़ा, कप-प्लेट, ईट आदि उत्पादन की योजना बताई। श्री राहुल बघेल ने सौर ऊर्जा के उपयोग से आत्मनिर्भर गांव एवं विभिन्न कुटीर उद्योगों पर प्रस्तुतीकरण दिया। उद्यमी श्री रविन्द्रकुमार धुरंधर ने कुपोषण से पीड़ित लोगों के लिए इंस्टेंट फूड उत्पाद की योजना पर अपना प्रस्तुतीकरण दिया। श्री अंकेश बंजारे ने आदिवासी कलाकारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म और वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने की योजना बताई तथा पुरूषोतम, अजय कुमार, सिद्धार्थ सिंह ने उच्च क्षमता वाले ड्रोन के माध्यम से कृषि फसलो की निगरानी की योजना के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सहकार भारती (छ.ग.) डॉ. लक्ष्मीकांत द्विवेदी ग्रामीण प्रौद्योगिकी और उद्यमिता फाउंडेशन के संचालक डॉ. आर. एन. पटेल, सीईओ श्री अग्रांशु द्विवेदी तथा उद्यमी उपस्थित थे।

हड़ताल में बैठे नगरीय निकाय के कर्मचारी

पुरानी पेंशन योजना बहाली, नियमितीकरण समेत कई मांगे

रायपुर। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना समेत 6 सूत्रीय मांग को लेकर तीन दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते निकायों में कामकाज ठप हो गया है। इन कर्मचारियों की मांग है कि नगरीय निकायों के कर्मचारियों को प्रतिमाह 1 तारीख को वेतन भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए।

कर्मचारियों की ये भी मांग है कि नगरीय निकायों में ठेका पद्धति समाप्त करते हुए प्लेसमेंट कर्मचारियों को नगरीय निकाय के माध्यम से वेतन भुगतान किया जाए। 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले निकाय के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण किया जाए। नगरीय निकायों में अन्य विभाग की भाति पुरानी पेंशन योजना शीघ्र ही लागू किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश निर्देश जिस तिथि से जारी हो उस तिथि से आदेश निर्देश सभी नगरीय निकायों में पूर्णत: लागू किया जाए।

नगरीय निकायों में मृतक कर्मचारी के परिवारों को शीघ्र ही संभाग स्तर में रिक्त पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किया जाए। नगरीय निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों को 12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चैनल निर्धारित करते हुए संभाग स्तर में रिक्त पद पर पदोन्नति की कार्यवाही शीघ्र की जाए। नगरीय निकायों के कर्मचारियों को 6 वें व 7वें वेतनमान की एरियर्स की राशि का भुगतान के लिए शीघ्र ही आदेश निकाला जाए। इन मांगों को लेकर निकाय के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं।

सीएम साय की अध्यक्षता में 20 सितंबर को होगी कैबिनेट बैठक

कई मुद्दों पर लिए जा सकते है अहम फैसले

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार 20 सितंबर सुबह 11:30 बजे से नवा रायपुर में महानदी भवन स्थित मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभाग सचिवों से कैबिनेट में मंजूरी योग्य प्रस्ताव समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह बैठक करीब एक माह बाद हो रही है, जिसमें राज्योत्सव आयोजन, धान खरीदी की शुरुआत, नई औद्योगिक नीति, और नक्सलवाद खत्म करने के लिए पुनर्वास नीति समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है।

बता दें कि इस बार भाजपा सरकार के सत्ता में वापसी के बाद पहला राज्योत्सव है, इस बार 1 नवंबर दीपावली के दूसरे दिन पड़ रहा है, इसलिए सरकार की 3 से 5 दिनों तक भव्य रूप से इसे आयोजित करने की योजना है। जिलों में भी एक या दो दिन के राज्योत्सव कार्यक्रमों का आयोजन संभव है। कैबिनेट की बैठक में 1 नवंबर से खरीफ सीजन की धान खरीदी की शुरुआत की घोषणा भी हो सकती है। इसके अलावा विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डाक्यूमेंट पेश किया जाएगा, जिसमें अगले पांच वर्षों के विकास का खाका तैयार किया जाएगा। साथ ही, नई औद्योगिक नीति और नक्सलवाद खत्म करने के लिए पुनर्वास नीति भी पेश की जा सकती है।

सीमेंट 45 रुपये हुई सस्ती, कंपनियों ने वापस लिया दाम

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब लोगों को सीमेंट को लेकर राहत मिल गई है। सीमेंट कंपनियों ने 45 रुपये दाम घटा दिए हैं। बता दें कि सीमेंट कंपनियों ने 50 रुपए दाम बढ़ा दिए थे, जिसे लेकर कांग्रेस समेत आम आदमी राज्य सरकार के खिलाफ विरोध पर उतर गए थे। इसके साथ ही बीजेपी के रायपुर सांसद समेत कई नेताओं ने नाराजगी जताई थी।

छत्तीसगढ़ में कंपनियों ने शनिवार को सीमेंट की कीमत 45 रुपये घटाने की घोषणा की। कंपनियों ने तीन सितंबर को सीमेंट की प्रति बोरी की कीमत 50 रुपये बढ़ाने की घोषणा की थी। चौतरफा दबाव के बाद कंपनियों ने दाम वापस ले लिया है। अब रिटेल में सीमेंट 255 से 265 रुपये प्रति बैग बिक रही है।

सीमेंट की दाम बढ़ने से रायपुर बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विरोध किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रतिस्पर्धा आयोग को पत्र लिखकर बढ़ी कीमत को वापस लेने की मांग की थी। सांसद अग्रवाल ने पत्र लिखा था कि छत्तीसगढ़ खनिज, लौह, कोयला ऊर्जा संसाधनों से भरपूर है। इसके बावजुद सीमेंट कंपनियों ने तीन सितंबर से कीमतों में एकाएक वृद्धि की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीमेंट कंपनियों ने एक कार्टल बनाकर सीमेंट की कीमतें 50 रुपए प्रति बोरी तक बढ़ा दी हैं, जो कि प्रदेश की जनता पर सीधा आर्थिक बोझ डाल रही है।

किसानों को मिला 6606 करोड़ रूपए का अल्पकालीन कृषि ऋण

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर राज्य के अधिक से अधिक किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण किया जा रहा है। प्रदेश में किसानों को अब तक राज्य सहकारी बैंकों के द्वारा 2058 सहकारी समितियों के माध्यम से लगभग 6606 करोड़ रूपए का अल्पकालीन ब्याज मुक्त कृषि ऋण वितरण किया गया है। इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा किसानों को 7300 करोड़ रूपए ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को उनके मांग और रकबे के अनुरूप अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जा रहा है। जबकि पिछले वर्ष आज की स्थिति में 6 हजार 544 करोड़ रूपए के अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित किए गए थे। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को खेती-किसानी की प्रारंभिक जरूरतों को पूरा करने तथा खेती-किसानी में सहूलियत प्रदान करने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना प्रारंभ किए गए हैं। इसके अलावा किसानों को साहूकारों के चंगुलों से बचाना इसका एक प्रमुख उद्देश्य था।

उप मुख्यमंत्री साव अमेरिका प्रवास से आज लौटेंगे स्वदेश

रायपुर। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव अमेरिका का अपना आठ दिवसीय अध्ययन प्रवास पूर्ण कर 19 सितम्बर को स्वदेश लौटेंगे। वे अमेरिकी समय के अनुसार 18 सितम्बर को सवेरे 09:05 बजे सेन फ्रांसिस्को से भारत के लिए रवाना होंगे। वे भारतीय समय के अनुसार 19 सितम्बर को दोपहर पौने तीन बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि उप मुख्यमंत्री श्री साव और लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह एशियन डेवलपमेंट बैंक के आमंत्रण पर विगत 10 सितम्बर से अमेरिका के अध्ययन प्रवास पर हैं।

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने अमेरिका में अपने आठ दिवसीय अध्ययन यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और सेन फ्रांसिस्को में सड़क एवं भवन निर्माण परियोजनाओं का भ्रमण किया। उन्होंने निर्माण विशेषज्ञों के साथ बैठक कर बड़ी निर्माण परियोजनाओं की प्लानिंग, डिजाइनिंग, निर्माण सामग्रियों, निर्माण तकनीकों तथा चरणबद्ध ढंग से उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी ली। उन्होंने विशेषज्ञों से कार्यस्थलों पर निर्माण कार्मिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर चर्चा की।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अमेरिका में निर्माण स्थलों के भ्रमण के दौरान वहां कार्यरत आर्किटेक्ट्स और इंजीनियरों से चर्चा कर प्रयुक्त सामग्री, धातु एवं मशीनरी की जानकारी ली। उन्होंने छत्तीसगढ़ में उन्नत सड़क परियोजनाओं और भवन निर्माण में आधुनिक तकनीकों व मशीनरी के उपयोग के संबंध में भी निर्माण विशेषज्ञों से चर्चा की।

न्यायधानी की सफाई व्यवस्था ठप

बिलासपुर। नगर निगम के सफाई कर्मियों के हड़ताल पर जाने से न्यायधानी बिलासपुर की सफाई व्यवस्था बुधवार को ठप रही। दो महीने से तनख्वाह नहीं मिलने से परेशान सफाई कर्मचारी आज से हड़ताल पर हैं। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में सफाई का ठेका दिल्ली की लायन्स सर्विस कंपनी के पास है, जिसके करीब 800 सफाईकर्मियों पर न्यायधानी की सफाई व्यवस्था टिकी हुई है। इन सफाई कर्मियों का कहना है कि दो महीने का वेतन बकाया है, जिसकी वजह से उन्हें परिवार चलाने में दिक्कत हो रही है। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि इन्हें महज 8 हजार रुपए वेतन मिलता है, ऐसे में अपनी तनख्वाह बढ़ाने को लेकर भी आवाज़ उठा रहे हैं।

देवेंद्र यादव से मिलने सेंट्रल जेल पहुंचे जीतू पटवारी

रायपुर। मध्यप्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात करने रायपुर के सेंट्रल जेल पहुंचे हैं। इसके बाद वे कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी सेंट्रल जेल में मौजूद हैं। बता दें कि बलौदाबाजार हिंसा मामले में करीब महीनेभर भिलाई विधायक देवेंद्र यादव जेल में बंद हैं।

इस दौरान जीतू पटवारी ने कहा, 2023 में जिस भावना से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार को चुना गया। मोदी की गारंटी को लेकर लोगों के बीच में गए थे। पिछले 8 महीने में एक भी काम उस भावना से नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में तानाशाही, बदलापुर चल रही है, जिसकी वजह से देवेंद्र यादव जेल में हैं। कांग्रेस उस विचार की पार्टी है, जो गांधीवादी तरीके से लड़ती है।

एमपी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, देश में बदलाव की लहर है। राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से वक्तव्य आए हैं, भाजपा के नेता और भाजपा लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में 500 थानों में गिरफ्तारी के लिए आवेदन दिए हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मध्यप्रदेश के भाजपा विधायक का कहना है कि कांग्रेस भाजपा शासित प्रदेशों में सरकार को अस्थिर करने का काम कर रही है, इस पर पलटवार करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस से बीजेपी को खतरा नहीं है। बीजेपी से बीजेपी को खतरा है। आप ही के अंदर इतनी अंतरकलह है कि आप एक दूसरे को हटाने चाहते हैं।

ध्वनि प्रदूषण: जिला प्रशासन का यही रवैया रहा तो हथखोज के समान आत्महत्या की घटनाएं रायपुर में भी होगी

अपनी असफलता को छुपाने के लिए गलत बयानी कर रहा प्रशासन, डॉक्टर गुप्ता ने रायपुर जिला प्रशासन से पूछे कई सवाल

रायपुर। ध्वनि प्रदूषण को लेकर जिला प्रशासन की असफलता पर रायपुर के ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कई प्रश्न उठाए हैं। डॉ गुप्ता ने बताया कि उन्हें एक डीजे संचालक ने जान से मारने की धमकी दी जिसकी लिखित शिकायत कल उन्होंने रायपुर जिला पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से मिलकर लिखित में की। उसके बावजूद भी आज कुछ समाचार पत्रों में एसपी का बयान छपा है कि एसपी साहब को शिकायत की जानकारी नहीं है। डॉक्टर गुप्ता ने पूछा है की 24 घंटे गुजर गए एफ.आई.आर. तो दर्ज नहीं कराई गई और गलत बयानी क्यों कर रहा है प्रशासन? डॉ गुप्ता ने चुनोती दी कि एसपी ऑफिस का विडियो रिकॉर्डिंग देखी जा सकती है जो कि प्रमाण है कि वो एसपी से मिले थे। उन्होंने पूछा प्रशासन डीजे संचालक पर कार्यवाही करने से क्यों बच रहा है?

डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तारतम्य में राज्य शासन द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद वाहनों पर स्पीकर रखकर बजाना प्रतिबंधित किया जा चुका है। परंतु अब गणेश पंडाल

वाले सड़कों पर डीजे और डीजे की तेज लाइट लगाकर घंटे डीजे बजा रहे हैं। शिकायत करने के बाद भी प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं करता। कल रात को शंकर नगर चौक में 7 बजे से यंग हिंदू गणेश उत्सव समिति द्वारा 10 बजे तक सड़क पर रखकर डेढ़ सौ डेसीबल पर डीजे बजाए गए। वहां ट्रैफिक में फंसे लोग फोटो भेज कर फोन करते रहे। कॉल सेंटर में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। रात 10 बजे पुलिस पहुंची परंतु दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं की, ना ही डीजे जप्त किये जो की प्रशासन की मिलीभगत बताता है। डॉक्टर गुप्ता ने मांग की की यंग हिंदू गणेश उत्सव समिति के सभी सदस्यों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत तत्काल कार्यवाही की जावे। डॉ गुप्ता ने चेताया कि निवासों के सामने गणेश पंडालों में बजने वाले कानफाडू साउंड स्पीकर पर अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो हथखोज में जैसी आत्महत्या की घटनाए हुई है वैसी रायपुर शहर में भी होगी जिसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा।

डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने उच्च न्यायालय में छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति द्वारा दायर याचिका के दौरान शपथ पत्र दिया था कि कुछ लोगों के विरुद्ध हाई कोर्ट के आदशानुसार, हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर अवमानना की कार्यवाही की जावेगी। परंतु अभी तक यह कार्यवाही क्यों नहीं की गई है? उल्लेखनीय है कि यंग हिंदू गणेश उत्सव समिति शंकर नगर के विक्की शादीजा और अन्य लोगों के नाम शपथ पत्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक ने में कोर्ट को बताए थे।

डॉक्टर गुप्ता ने पूछा कि 2022 में गृह विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने समस्त कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को आदेशित किया है कि बिना अनुमति के कोई भी पंडाल सड़क पर ना लगे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने रायपुर शहर में एक भी अनुमति गणेश पंडाल लगाने और स्वागत द्वार लगाने के लिए नहीं दी। जिला प्रशासन को बताना चाहिए कि जब उन्होंने अनुमति नहीं दी तो रायपुर शहर में सैकड़ों पंडाल सड़कों पर लगकर यातायात व्यवस्था को ध्वस्त क्यों कराया गया? इससे अनावश्यक वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण भी जनता को मजबूरीवश सहना पड़ा। जबकी एनजीटी ने लिए छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति की याचिका में जनता को होने वाले कष्ट को देखते हुए आदेशित कर रखा है कि रायपुर शहर की सडकों पर पंडाल और स्वागत द्वार लगते पाये जाने पर उसे तत्काल हटाना है। डॉ गुप्ता ने पुछा कि प्रशासन एनजीटी के आदेश का पालन क्यों नहीं करना चाहता?

राहुल भूल गए कि उनकी कर्मभूमि भारत है

अरविन्द मोहन

भारत जोड़ो और न्याय यात्रा जैसे नामों से निकाली लंबी यात्राओं और फिर 'इंडिया' गठबंधन (आधा-अधूरा ही सही) बनाकर नरेंद्र मोदी और भाजपा को गंभीर चुनौती देने के बाद से राहुल गांधी का सितारा निरंतर बुलंदी की तरफ गया है। लोकसभा चुनाव के परिणाम में कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन को जितनी जीत नहीं मिली, उससे ज्यादा बड़ा राजनीतिक संदेश नरेंद्र मोदी का कद घटने से गया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी अपने विदेशी दौरों के सहारे अपनी खोई इमेज को सहारा देने की कोशिश कर रहे थे और उनकी सरकार अपने पहले 100 दिन के कामकाज का शोर मचाने की तैयारी कर रही थी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने विदेशी दौर, खासकर अमरीका के दौरे से जो संदेश दिया, वह उनकी और कांग्रेस की आगे बढने के रफ्तार को कम कर दे तो हैरानी नहीं होगी। राहुल ने अमरीका में कई ऐसी बातें कहीं, जिनका असली मंच भारत है। और भारत सिर्फ कहने या दावा करने का मंच नहीं है, विपक्ष के नेता के लिए कर्मभूमि भी है। अगर उनको गंभीरता से लगता है कि लोकसभा चुनाव में धांधली हुई थी, तो इस सवाल को अमरीका की जगह भारत में और चुनाव के समय या उसके ठीक बाद उठाना था और फिर इसके पक्ष में राजनीतिक और कानूनी लड़ाई भी लडनी थी। फिर उन्होंने अल्पसंख्यकों की तकलीफ का सवाल भी अमरीका में उठाया। कांग्रेस लगातार और बिना डगमगाए मुसलमानों का या धर्मनिरपेक्षता का सवाल उठाती रही है और इस बात को मुसलमान स्वीकारते हैं। राहुल और उनकी कांग्रेस ने मुसलमानों को जुबानी समर्थन दिया लेकिन सी.ए.ए. विरोधी मजबूत और अहिंसक आंदोलन को भी अपना शक्ति भर समर्थन देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। उलटे खुद राहुल साफ्ट हिन्दुत्व की राजनीति करते दिखे। उनको यह भी याद नहीं रहा कि गांधी और कांग्रेस के ज्यादातर हिंदू नेताओं ने अपने हिन्दुत्व को चलाते हुए किस तरह धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव की राजनीति को आगे बढ़ाया। पर अमरीका जाकर उन्होंने जो सबसे अजीबो-गरीब बयान दिया, वह सिखों के संदर्भ में था। सिखों द्वारा अपनी धार्मिक पहचान के साथ जीवन जीने, प्रार्थना-अरदास करने में कोई दिक्कत हो रही हो, यह कहना कुछ ज्यादा ही 'सैकुलर' बनना है। कहीं कोई एकाध मामला होगा भी तो उसका आम सिखों के लिए ज्यादा मतलब नहीं है। यह कहते हुए राहुल कुछ बड़े उदाहरण देते या कांग्रेस द्वारा इस सवाल पर देश के अंदर किए गए किसी आंदोलन का हवाला देते, तब जाकर बात समझ आती। लेकिन राहुल का यह दावा करना सबसे अटपटा लगा कि आज विपक्ष अर्थात वे शासन का एजैंडा तय करते हैं। सरकार उनके द्वारा उठाए मुद्दों को ध्यान में रखकर फैसले लेती और बदलती है। विपक्ष के दबाव या चुनावी धक्का खाने के बाद भाजपा की अगुवाई वाली यह सरकार जरूर फूंक-फूंक कर फैसले ले रही है और कई विवादास्पद फैसले ताक पर डाल दे रही है। पुरानी पैंशन योजना, वक्फ बोर्ड संबंधी विधेयक पर ही नहीं, जातिवार जनगणना पर सरकार का घिरना उनके गिनवाने के मुद्दे हैं। पर इसमें जितना योगदान उत्साह में आए विपक्ष का है, उससे ज्यादा एन.डी.ए. के घटक दलों का है। शुरू में तो तेलुगु देशम और जनता दल-यू का ही मामला था, अब तो चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, ओमप्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे लोग भी दबाव की राजनीति खेलने लगे हैं और सरकार उनके दबाव से भी फैसले बदल रही है या ले रही है। उसे के.सी. त्यागी को प्रवक्ता पद से हटवाना और चिराग से अलग से बात करनी पड़ती है। यह एक व्यक्ति के राज की जगह गठबंधन की राजनीति का परिणाम ज्यादा है, राहुल गांधी के उत्साह और आक्रमण का कम। अगर उनकी वजह से ऐसा हो रहा होता, तब भी यह दावा कुछ बड़बोलापन लगता है। दूसरी तरफ इतने कम समय में ही राहुल की खुद की कमजोरियां भी ज्यादा उजागर हुई हैं।

चुनौतियों को चुनौती देकर विजय हासिल करने वाले मोदी

नीरज कुमार दुबे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जन्मदिन पर चारों ओर से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए माँ भारती प्रधानमंत्री मोदी को और शक्ति व सामर्थ्य प्रदान करें। वर्ष 1950 में 17 सितंबर के दिन एक साधारण परिवार में जन्मे नरेन्द्र दामोदर दास मोदी का सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना इस बात का संकेत है कि यदि व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति और अपनी मंजिल तक पहुंचने का जज्बा हो, तो वह मुश्किल से मुश्किल हालात को आसान बनाकर अपने लिए नये रास्ते बना सकता है। हम आपको बता दें कि 26 मई 2014 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मोदी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलायी थी। पांच बरस बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर लोकसभा चुनाव जीता और उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की। इस साल नौ जून को उन्होंने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिये प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद मोदी पंडित जवाहर लाल नेहरू के बाद लगातार तीन बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति हो गए हैं। मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जिन्होंने आजाद भारत में जन्म लिया था।

देखा जाये तो देश को आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ाने वाले, देश को गुलामी की मानसिकता से निजात दिलाने वाले, मुश्किल से भी मुश्किल समय में देश को कुशल नेतृत्व देने वाले, बात महामारी की हो या आतंकवाद की...रणनीति और साहस के साथ उनका खात्मा करने वाले, विस्तारवादी ताकतों की सारी हेकड़ी निकालने वाले, देश को अगले 25 सालों के लिए नव-संकल्प दिलाकर सबको साथ लेकर, सबको विश्वास में लेकर आगे बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व कौशल की आज पूरी दुनिया कायल है। मोदी है तो मुमकिन है, यह कोई महज चुनावी नारा नहीं बल्कि आश्वस्ति का वह भाव है जो देश की जनता के मन में है। देश की जनता सिर्फ इसी बात से निश्चिंत है कि मोदी हैं तो हमारे देश की संप्रभुता और अखण्डता को कोई आंच नहीं आ सकती। जनता बार-बार देख चुकी है कि कोई भारत को छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं यह बात सिर्फ मोदी कहते भर नहीं हैं इसे समय-समय पर हकीकत भी बना कर दिखाते हैं।

गुजरात के वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले से लेकर वर्ल्ड स्टेज पर दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शुमार होने तक और एक बार फिर ग्लोबल लीडर अप्रुवल रेटिंग में सबसे आगे रहने तक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा बड़ी रोचक और प्रेरणादायक रही है। नरेंद्र मोदी इस मामले में पहले प्रधानमंत्री हैं जिसने गरीबी को सबसे करीब से देखा है। जिसकी माँ दूसरों के घरों में काम करती हो, जिसने खुद कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेची हो, जिसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दो जोड़ी कपड़ों में गुजारा हो, जिसने हिमालय की चोटियों पर बरसों संन्यासी के रूप में गुजारे हों, जिसने मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात को ऐसा चमकाया हो कि दुनिया भारत के इस राज्य की चकाचौंध से जुड़ने के लिए खुद आतुर हुई हो, जिसने प्रधानमंत्री के रूप में भारत को गरीबी और निराशा की स्थिति से निकाला हो और जो देश को एकजुट कर नये भारत और विकसित भारत की परिकल्पना साकार करने के लिए निकल पड़ा हो, उस हस्ती का देश-दुनिया वंदन कर रही है। वाकई ऐसे जुझारू, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, भारत की संस्कृति के प्रचारक और राष्ट्रभक्त जनसेवक बिरले ही होते हैं। अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद की लगभग समाप्ति कर कश्मीरी युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने की बात हो या फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद और कुछ राज्यों में आधार रखने वाले माओवाद पर काबू पाने की बात हो, मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में पूर्णत: शांति बनी हुई है और हर जगह सिर्फ कानून का राज है।

नरेंद्र मोदी को जनप्रतिनिधि के रूप में विभिन्न पदों पर रहते हुए 21 साल से ज्यादा समय हो चुका है लेकिन देखिये उनके पास अन्य नेताओं की तरह ना तो आलीशान बंगला है, ना ही बड़े-बड़े बैंक बैलेंस हैं और ना ही चमचमाती कारें हैं। हाँ, उनके पास भारत की जनता का प्यार जरूर है तभी तो चुनावों के समय जनता खुद ही नारा लगाती है- नमो नमो, मोदी मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी घर घर मोदी लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने देश को जो बड़े नारे या फिर कहिये सूत्रवाक्य दिये वह हैं- एक भारत, श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। नरेंद्र मोदी ने अपने लिए बड़ा घर बनाने की जगह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रिकॉर्ड संख्या में जरूरतमंदों के सिर पर छत प्रदान की। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र या अपने गृहराज्य की चिंता करने की बजाय देश को समान रूप से विकास की ऐसी ढेरों परियोजनाएं प्रदान कीं जिससे नये भारत का निर्माण चारों ओर होता दिख रहा है।

भारत का पहला वॉर मेमोरियल, सेंट्रल विस्टा परियोजना, नया संसद भवन, नये संसद भवन में हमारा सेंगोल, भारत मंडपम, यशोभूमि आदि राष्ट्र इमारतें मोदी के कार्यकाल में ही साकार हुईं। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, स्वच्छ भारत, जीएसटी, वन रैंक वन पेंशन, सीडीएस, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया अभियान, नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के वादे भारत में बरसों से सुने जाते थे लेकिन यह सब साकार मोदी सरकार के कार्यकाल में ही हुए। यही वह सरकार है जिसने उद्योगों को मजबूती प्रदान करने के लिए तमाम कदम उठाये, उद्योगों की स्थापना संबंधी प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया, मंजूरियां प्रदान करने की प्रक्रिया को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया, युवाओं को रोजगार पाने की जद्दोजहद में जुटने की बजाय उन्हें रोजगार प्रदान करने लायक स्थिति में पहुँचाने के लिए तमाम योजनाओं को पेश किया, कोरोना के कहर से देश को बचाने के लिए भारत में वैक्सीन के निर्माण को प्रोत्साहित भी किया तथा दुनिया में सबसे ज्यादा और तीव्र गति से वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया, संकट के समय महीनों तक गरीब जनता को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया। यही नहीं ओलम्पिक, पैरालम्पिक और राष्ट्रमंडल खेलों के सभी पदक विजेताओं और प्रतिभागी खिलाड़ियों का हौसला प्रधानमंत्री ने निजी रूप से बढ़ाया। विभिन्न क्षेत्रों में मुकाम हासिल करने वालों से बात कर उनका हौसला बढ़ाने की बात हो, युवाओं का विभिन्न अवसरों पर मार्गदर्शन करने की बात हो, छात्रों से परीक्षा पर चर्चा कर उनका हौसला बढ़ाने की बात हो...नरेंद्र मोदी से पहले किसी प्रधानमंत्री ने यह काम नहीं किया।

भोलेनाथ के भक्त और काशी के जनसेवक मोदी ने रामनगरी अयोध्या में श्रीराम का दिव्य और भव्य मंदिर बनवा कर हिन्दुस्तान की जनता का सैंकड़ों वर्षों पुराना सपना साकार कर दिया तो मोदी सरकार के कार्यकाल में ही अल्पसंख्यक मंत्रालय ने मुस्लिमों के लिए इतनी योजनाएं पेश कीं कि आज यह वर्ग पहले की अपेक्षा ज्यादा पढ़ा-लिखा और संपन्न नजर आ रहा है। मोदी ने इस देश में बरसों से चल रही तुष्टिकरण की राजनीति को तो समाप्त किया ही मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के अभिशाप से भी मुक्ति दिलाई। आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन हो या फिर रक्षा बंधन या भैया दूज का त्योहार, मुस्लिम महिलाएं मोदी को भाई के रूप में राखी भेजती हैं, तिलक भेजती हैं। प्रधानमंत्री स्वयं कई बार अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबुद्ध लोगों से बात कर उनकी समस्याएं हल करने की दिशा में कदम उठा चुके हैं। यही कारण है कि देश में लोकसभा और विधानसभा की कई ऐसी सीटें हैं जो अल्पसंख्यक बहुल होने के बावजूद भाजपा के पास हैं। यह दर्शाता है कि मुस्लिमों को वोट बैंक के रूप में देखने वालों के दिन अब लद चुके हैं।

इस देश में दलितों और पिछड़ों को भी सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखा जाता था लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनकी सामाजिक और आर्थिक दशा में बड़े बदलाव आये हैं। सबको याद होगा कि प्रयागराज के कुंभ मेले में स्वच्छता कर्मियों के पैर खुद प्रधानमंत्री ने धोये थे और उन्हें सम्मानित किया था। कोई भी परियोजना साकार हो, मोदी उसमें लगे श्रमिकों का सम्मान करना कभी नहीं भूलते। कारीगरों और मजदूरों का काम पहले निर्माण के बाद खत्म समझा जाता था लेकिन मोदी के कार्यकाल में इन श्रमिकों को सम्मान मिल रहा है। यही नहीं, आज पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने का काम जितना नरेंद्र मोदी ने किया है उतना आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। गांवों और किसानों की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए ना सिर्फ अनेकों योजनाएं पेश कीं बल्कि उनके क्रियान्वयन पर खुद निगाह भी रखी। गरीब किसानों की मदद के वादे तो पहले भी किये जाते थे लेकिन नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान योजना के जरिये ना सिर्फ उनकी आर्थिक मदद की बल्कि तमाम तरह की फसलों का एमएसपी समय-समय पर बढ़ाकर उन्हें और सशक्त भी किया।

मोदी भ्रष्टाचार, परिवारवाद जैसी बुराई का कचरा तो साफ कर ही रहे हैं साथ ही वह स्वच्छ भारत के लिए कितने गंभीर रहते हैं यह देश कई बार देख चुका है। गंदगी दिखे तो झाड़ू लगा देना, समुद्र तट पर जायें तो कचरा एकत्र कर उसे डस्टबिन में डालना और किसी परियोजना के उद्घाटन के समय सिर्फ रिब्बन ही नहीं काटना बल्कि कचरा दिखे तो उसे भी उठा देना...ऐसा सिर्फ आज तक एक ही प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। प्रधानमंत्री योग से निरोग रहने का संदेश ही नहीं देते उसे खुद भी जीवन में अपनाते हैं। सेना के किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो सैन्य वर्दी को शान से पहनते हैं। मोदी से पहले किसी अन्य प्रधानमंत्री ने जनता से मन की बात अगर की थी तो सिर्फ चुनावों के समय की थी लेकिन मोदी हर महीने के अंत में रेडियो के माध्यम से अपने मन की बात रखते हैं। यही कारण है कि मोदी के मन से वाकिफ जनता उनके एक आह्वान पर उठ खड़ी होती है। मोदी ने कोरोना काल में जो-जो आह्वान किये देश की जनता उनसे जुड़ी, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया तो देश के प्रत्येक नागरिक ने मिलकर उसे सफल बनाया।

मोदी वैसे तो भारत के प्रधानमंत्री हैं लेकिन वह अपने काम से वैश्विक नेता की छवि रखते हैं। विदेशी रेटिंग एजेंसियों के अनुसार मोदी की ग्लोबल अप्रुवल रेटिंग में उनके आसपास दुनिया का कोई नेता नहीं है। मोदी ने भारतीय विदेश नीति को जिस तरह आगे बढ़ाया है उससे पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। दुनिया के किसी भी कोने में संकट हो तो वह हल के लिए भारत की ओर देखता है। भारत में विपक्ष भले राजनीतिक मजबूरी के चलते मोदी की विदेश नीति की सराहना नहीं करे लेकिन दुनिया मोदी की नीतियों को सराह रही है।

मोदी राष्ट्र हित में फैसले लेने के लिए राजनीतिक नुकसान की परवाह कभी नहीं करते इसलिए वह देश के लिए कई साहसिक निर्णय ले पाये हैं। प्रतिदिन 24 में से 18 घंटे काम करने वाले भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के लिए देश सेवा ही सबकुछ है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद तक पहुँचने का उनका सफर हमारे लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है जहाँ सामान्य परिवार से जुड़ा व्यक्ति भी शीर्ष पद तक पहुँच सकता है। मोदी देश को विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना ही चुके हैं। उम्मीद है कि उनके ही नेतृत्व में हम पहले नंबर पर भी पहुँचेंगे। मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में जिस तेजी से देश को आगे बढ़ाने का काम किया है उससे देशवासियों का विश्वास एनडीए सरकार के प्रति और मजबूत हुआ है।

बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले अपना जन्मदिन नहीं मनाते हों लेकिन देश उनके जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाता है क्योंकि भारत की जनता यही चाहती है कि उसे बरसों बाद जो सशक्त नेता मिला है वह अनंत काल तक नेतृत्व करता रहे।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

प्रमाण-संग्रहाध्यायः (दूसरा अध्याय)

गतांक से आगे...

सायणीय ऋग्वेदउपोद्घात- (36) षडङ्गवत्पुराणादीनामपि याज्ञवल्क्येन स्मर्यते । वेदार्थज्ञानोपयोगो (सायण भाष्य)

अर्थात् - शिक्षा कल्पादि वेदाङ्गों की तरह पुराण और उप-पुराणों को भी वेद का अर्थ जानने के लिये याज्ञवल्क्य जी ने अपनी स्मृति में उपयोगी भाना है।

(37) ऐतरेयतैत्तिरीयकाठकादिशाखासूक्तानि हरिश्चन्द्र- नचिकेताद्युपाख्यानानि धर्मब्रह्मावबोधोपयुक्तानि तेषु तेष्वितिहासग्रन्थेषु स्पष्टीकृतानि, उपनिष- दुक्ताश्च सृष्टिस्थितिलयादयो ब्राह्मपाद्मवैष्णा- वादिपुराणेषु स्पष्टी कृता:। (सायण भाष्य)

वेद-शाखाओं में जो अर्थात् - ऐतरेय तैत्तिरीय काठक आदि हरिदत्चन्द्र नचिकेता आदि के धर्म और ज्ञानोपयोगी उपाख्यान लिखे हैं वे महाभारतादि में स्पष्ट किये गये हैं, और उपनिषद्वर्णित सृष्टि, पालन, प्रलय आदि विषय ब्राह्म-पुराण पद्म-पुराण और विष्णु-पुराण आदि में स्पष्ट किये गये हैं।

(38) इति सृष्ट्यादे: पुराणप्रतिपाद्यत्वावगमात् । (सायणभाष्य)

अर्थ - इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय आदि पुराणों का प्रतिपाद्य विषय जानने से ।

(39) उक्तप्रकारेण पुराणादीनां वेदार्थज्ञानोपयोगाद् विद्यास्थानत्वं युक्तम्। (सायणभाष्य)

अर्थ - इस प्रकार पुराण उपपुराण भी वेदार्थ चानने में उपयोगी होने से %विद्या के स्थान% ठीक ही हैं।

(40) एतै: पुराणादिभिश्चतुर्भिर्भावद्यास्थानैरुपबृहिताया विद्याया ग्रहणेऽधिकारविशेष:, शाखान्तर्गतैश्चतु- भिर्मन्त्रैरुपर्शित: । (सायणभाष्य)

अर्थ- पुराणादि चार विद्यास्थानों द्वारा उपबृंहित विद्या के ग्रहण में अधिकार-विशेष अन्य शाखाओं के चार मन्त्रों में दिखाया है। **क्रमश: ...**

सुनीता विलियम्स

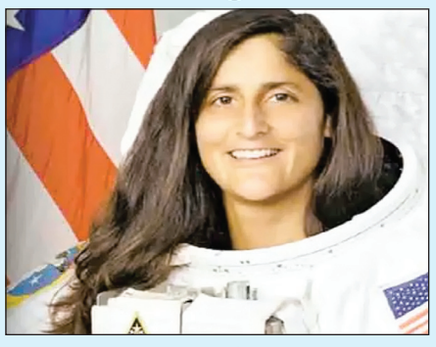

भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स आज 59 वर्ष की हो गई हैं। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहायो के यूक्लिड शहर में हुआ था। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता 195 दिन से भी ज्यादा दिन तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बना चुकी हैं।

सुनीता विलियम्स पांड्या के पिता डॉ. दीपक एन.पांड्या भारत के गुजरात के रहने वाले हैं और उनकी मां बॉनी जालोकर पांड्या स्लोवेनिया से हैं। जब सुनीता 1 साल की थी, तो उनके पिता अहमदाबाद से अमेरिका के बोस्टन में आकर बस गए। सुनीता विलियम्स के एक बड़े भाई जय थॉमस पांड्या और एक बड़ी बहन डायना एन पांड्या हैं। सुनीता का विवाह माइकल जे. विलियम्स से हुआ। वे सुनीता विलियम्स के सहपाठी रह चुके हैं।

सुनीता विलियम्स ने मैसाचुसट्स में नीधम हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी की है। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी से फिजिकल साइंस में बैचलर और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री हासिल की है।

सुनीता विलियम्स को 1987 में अमेरिकी नौसेना में शामिल किया गया। छह महीने की अस्थायी असाइनमेंट के बाद उनको बेसिक डाइविंग अफसर नियुक्त किया गया। 1998 में सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष यात्रा प्रशिक्षण लेना शुरू किया था।

सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में 195 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड बनाया था।

सुनीता विलियम्स का जून 1998 में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ और प्रशिक्षण शुरू हुआ। जून, 1998 से नासा से जुड़ी सुनीता ने अभी तक कुल 30 अलग-अलग अंतरिक्ष यानों में 2770 उड़ानें भरी हैं, जिसमें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 'नासा (1998) मिशन एसटीएस 116, अभियान 14, अभियान 15, एसटीएस 117, सोयुज टीएमए-05 एम, अभियान 32, अभियान 33 उपलब्धियां शामिल हैं।

सुनीता विलियम्स को सन् 2008 में भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें ह्यूमैनिटेरियन सर्विस मेडल,नेवी एंड मैरीन कॉर्प एचीवमेंट मेडल, नेवी कमेंडेशन मेडल (2) जैसे कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है।

सुनीता विलियम्स विभिन्न अभियानों में कुल 321 दिन 17 घंटे और 15 मिनट अंतरिक्ष में रहीं। विलियम्स कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, जिनकी कोलंबिया के अंतरिक्ष यान दुर्घटना में मौत हो गई थी।

चीन पर कभी यकीन नहीं किया जा सकता

अशोक मधुप

लगातार चार साल से चले आ रहे भारत चीन के बीच तनाव के कम होने के संकेत हैं। भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर हाल में घटनाक्रम बहुत तेजी से घटा है। चीन भारत सीमा से सेना का पीछे हटना बहुत अच्छा है किंतु चीन की बात पर आंख मूंदकर यकीन नहीं किया जा सकता। समझौते करने के बाद अपनी बात से मुकरना उसकी आदत रही है। धोखा देना चीन का चरित्र है। उस पर पूरी तरह से नजर रखनी होगी। उसकी चाल के अनुरूप हमें अपना व्यवहार और तैयारी करना होंगी।

भारत चीन सीमा विवाद के सुलझने के संकेत 12 सितम्बर को ही सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स एनएसए लेवल की समिट के साइडलाइन्स पर हुई उस बैठक के दौरान ही दिख गए थे जो एनएसए अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से बैठक के बाद जारी प्रेस नोट में इस बात का जिक्र था कि दोनों देशों ने बचे हुए क्षेत्रों में भी पूर्ण डिसएंगेजमेंट की दिशा में काम करने को लेकर सहमति जताई है। जानकार मानते हैं कि गतिरोध दूर करने करने की दिशा में ले जाने की प्रक्रिया एकाएक नहीं होती। इसके लिए बैकग्राउंड में काम होता रहता है ।

ओआरएफ में फेलो और चीन मामलों के जानकार कल्पित मणकिकर कहते हैं कि ऐसा एक

लंबी प्रक्रिया के तहत होता है। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और दोनों देशों के विदेश मंत्री लगातार मुलाकात करते आ रहे हैं। पिछले चार सालों से बॉर्डर मुद्दों को सुलझाने को लेकर कोशिशें लगातार हो रही है। सेना के कमांडर स्तर पर बातें अलग से होती रही हैं। भारत और चीन दोनों की ओर से इस तरह की कोशिशें की जा रही थी। हालांकि अब जो दिख रहा है, उसके मद्देनजर इस तरह की कोशिशें क्या दिशा लेंगी, इसे लेकर अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में ही रहा जा सकता है। बॉर्डर पर आए गतिरोध के मद्देनजर विदेश मंत्रियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठकें किए जाने का एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्वी लद्दाख में सीमा मुद्दे पर 12 सितम्बर को कहा कि सैनिकों की वापसी से संबंधित मुद्दे लगभग 75 प्रतिशत तक सुलझ गए हैं लेकिन बड़ा मुद्दा सीमा पर बढ़ते सैन्यीकरण का है। जिनेवा में थिंकटैंक के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जून 2020 में गलवन घाटी में हुए टकराव ने भारत-चीन संबंधों को समग्र रूप से प्रभावित किया।

जयशंकर ने कहा कि विवादित मुद्दों का समाधान ढूंढ़ने के लिए दोनों पक्षों में बातचीत चल रही है। हमने कुछ प्रगति की है। मोटे तौर पर सैनिकों की वापसी संबंधी करीब तीन-चौथाई मुद्दों का हल निकाल लिया गया है। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि हम दोनों ने अपनी सेनाओं को एक-दूसरे के करीब ला दिया है और इस लिहाज से सीमा का सैन्यीकरण हो रहा है।

सूत्रों का कहना है कि भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में कुछ टकराव वाले बिंदुओं पर गतिरोध बना हुआ है। भारत कहता रहा है कि सेना के पूर्व स्थान पर पहुंचे बिना सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति नहीं होगी, चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं हो सकते। जयशंकर ने कहा कि 2020 में जो कुछ हुआ, वह कुछ कारणों से कई समझौतों का उल्लंघन था जो अभी भी हमारे लिए पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया और स्वाभाविक रूप से जवाबी तौर पर हमने भी अपने सैनिकों को भेजा।

2020 की झड़प के बाद से दोनों देश सीमा पर बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा के रूप में भी जाना जाता है। भारत द्वारा उच्च ऊंचाई वाले हवाई अड्डे तक एक नई सड़क का निर्माण चीनी सैनिकों के साथ 2020 में होने वाली घातक झड़प के मुख्य कारणों में से एक माना जा रहा है ।

इस बार चीनी सेना के सीमा से पीछे हटने का कारण चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य वांग काबयान भी है। उन्होने इस बात पर जोर दिया कि अशांत विश्व का सामना करते हुए, दो प्राचीन पूर्वी सभ्यताओं और उभरते विकासशील देशों के रूप में चीन और भारत को स्वतंत्रता पर दृढ़ रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि एकता और सहयोग का चयन करना चाहिए तथा एक-दूसरे को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। वांग ने उम्मीद जताई कि दोनों पक्ष व्यावहारिक दृष्टिकोण के जरिए अपने मतभेदों को उचित ढंग से हल करेंगे और एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने का उचित तरीका ढूंढेंगे। चीन-भारत संबंधों को स्वस्थ, स्थिर और सतत विकास के रास्ते पर वापस लाएंगे। इतना सब हो रहा है पर जरूरी यह है कि दोनों का मई 2020 की यथास्थिति पर वापस लौटना ही समाधान है। निश्चित रूप से पीछे हटना समाधान नहीं है। यदि निश्चित रूप से समाधान के रास्ते पर चले तो भारत नुकसान में ही रहेगा। इन सब को देखकर भारत को चलना होगा। मई 2020 की स्थिति पर चीन सहमत होगा, ऐसा नही लगता।

आज का इतिहास

1957 अमेरिका ने नेवादा के रेगिस्तान में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया।
1960 चब्बी चेकर का द ट्विस्ट के साथ नंबर 1 रिकॉर्ड है। इस डांस फॉर्म के लिए दुनिया भर में डांस का क्रेज शुरू हुआ।
1964 मॉन्टैग्नार्ड्स द्वारा वियतनाम के आर्पी रिपब्लिक ऑफ न्ग्येन खान में शासन करने वाले सशस्त्र विद्रोह के कारण 70 जातीय वियतनामी सैनिक मारे गए।
1970 दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफ़ील्ड फेस्टिवल, पहला ग्लेस्टोनबरी फेस्टिवल, इंग्लैंड के ग्लासनबरी में माइकल एविस के खेत में आयोजित किया गया था।
1970 ग्रीक छात्र कोस्तास जॉर्जकिस ने जॉर्जियोपाप्पोपोलोस के यूनानी सैन्य जंता के खिलाफ विरोध के रूप में जेनोवा, इटली में खुद को आग लगा ली।
1973 सोवियत संघ ने सफल भूमिगत परमाणु परीक्षण किया।
1974 होंडुरास मे समुद्री तूफान फिफी के कहर से 5000 लोग मारे गए।
1982 स्कॉट फाहमैन ऑनलाइन संदेश का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति बने।
1983 सेंट किट्स और नेविस एक स्वतंत्र राज्य बने।
1985 मैक्सिको सिटी में 8.1 एमएल का भूकंप आया, जिसमें कम से कम 9,000 लोग मारे गए और 100,000 बेघर हो गए।
1985 मेक्सिको सिटी में भूकंप से भारी तबाही हुई। जिसमें तीन राज्य तबाह हो गए थे और करीब 10,000 लोग मारे गए।
2006 अंतरिक्ष यान अटलांटिस की वापसी में एक दिन की देरी है क्योंकि अज्ञात वस्तु को शटल के पास तैरते हुए देखा जाता है।
2006 रॉयल थाई सेना ने थाईप्राइम मिनिस्टर थाकसिन शिनावात्रा की निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंका, जब वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के चुनाव के लिए न्यूयॉर्क शहर में थीं।

रायपुर में गणेशोत्सव का इतिहास

गोकुल सोनी

साथियो, रायपुर में गणेशोत्सव का इतिहास काफी पुराना है। यह कब से शुरू हुआ, किसी को सही जानकारी नहीं है। कुछ जानकार बताते हैं रायपुर में पहले सिर्फ एक ही मूर्तिकार थे उनका नाम था गोविंदराव गिरहे। वे कंकालीपारा में मूर्ति बनाया करते थे, साथ ही वे बहुत अच्छे पेंटर भी थे।

गोविंदराव जी के दो शिष्य थे नारायणराव (बूढ़ापारा) और मुकुंदलाल यादव। दोनो उनके पास मूर्ति बनाना और पेंटिंग करना सीखा करते थे। मुकुन्दलाल जहां अच्छे मूर्तिकार थे वहीं नारायणराव अच्छे पेंटर थे। बाद में दोनों ने एक दूसरे की कला को सीखने का प्रयास किया। यानि मुकुंदलाल, नारायण राव को मूर्ति बनाने सिखाते वहीं नारायण राव मुकुंदलाल को पेंटिंग बनाना सिखाया करते थे। धीरे-धीरे मुकुंदलाल दोनो कला यानी मूर्ति बनाना और पेंटिंग करना सीख गये किन्तु नारायण राव मूर्ति बनाना नहीं सीख पाये। हां ये जरूर हुआ कि रोज-रोज देखकर नारायण राव की पत्नी लक्ष्मीबाई मूर्ति बनाना सीख गयी। फिर लक्ष्मीबाई ने कई वर्षों तक इस काम को व्यवसाय के रूप में अपना लिया।

नारायणराव के कई शिष्य हुये- मोहनलाल यादव, नारायण यादव (कुशालपुर) परस पेंटर जिसने गुढियारी में ऐतिहासिक नारियल का गणेश बनाया था। रहीस पेंटर रामनगर, माधव पेंटर, घनश्याम फूटान, हेनुराम सोन, केशव साहू। वहीं मुकुन्द लाल के भी कुछ शिष्य थे जिसमें रेखराज ध्रुव (मंदिर हसौद) नरेश पेंटर, श्याम पेंटर और रामनारायण यादव (पुत्र) इस तरह से प्रदेश मूर्तिकारों की संख्या बढ़ती गयी।

सुखरू लोहार और महरूदाऊ

रायपुर में पहले छोटी मूर्ति रखने का रिवाज था। लोहार चौक में सुखरू लोहार पारंपरिक रूप से गणेश स्थापना करते थे। उनकी मूर्ति हर साल एक जैसी होती थी। कहते हैं वे मूर्ति को विसर्जित कर सजावट सामग्री को आने वाले वर्ष के लिये सुरक्षित रख दिया करते थे। इनकी एक विशेषता थी वे हर वर्ष गणेश मूर्ति के सामने एक छोटी पानी की टंकी बनाते और उसमें सांप जैसे दिखने वाली मछली जिसे स्थानीय बोली में डूडुंग मछरी करते हैं डाल देते थे. यही मछली यहां बच्चों का आकर्षण का केन्द्र बनी रहती थी । इसी के ठीक बगल में मरउ दाऊ जी गणेश स्थापना करते थे। इनकी विशेषता थी, वे सजावट में चारो ओर कांच से सजावट करते थे इसलिये इसे कांच वाले गणेश भी कहते थे।

रामरतन बेरिया की सजावट ने इतिहास रचा

गणेश सजावट का क्रेज उस समय और बढ़ा, जब रामरतन बेरिया ने गुढियारी पड़ाव में एक विशाल झांकी बनायी । फलों की टोकरी, जूट की बोरियां और पालीथीन से उसने ऐसी झांकी बनायी जो देखने से उभरी हुई पेंटिंग की तरह दिखाई देता था। इस झांकी को देखने पूरे गुढियारी में मेला जैसा माहौल बन जाता था। रामरतन बेरिया रायपुर के ही रहने वाले थे लेकिन वह मुंबई में जाकर फिल्मों का सैट बनाना सीख गये थे ।जिसका खूबसूरत प्रयोग वे गणपति सजावट में करते थे.

हाथ पैर चलाने वाले मूर्ति

फिर शुरू हुआ मूवमेन्ट वाली झांकी का सिलसिला, इस झांकी में सजावट में रखे पुतलों के हाथ-पैर चलते थे। इसे देखने को भी भीड़ लगने लगी।

गुफा में गणेश

इसके बार आया झांकी में गुफा बनाने का चलन, गोलबाजार, रामसागरपारा में दो तीन मकानों को मिलाकर ऐसी गुफा बनाते थे कि दर्शनार्थी नदी, पहाड और सबको लांघ कर गणेश प्रतिमा का दर्शन करते थे। गुढियारी में ही नारियल से बने गणेश ने सारे कीर्तिमान तोड दिये। यह अपने ढंग का अनोखा प्रयोग था जो बहुत सफल रहा। इसे देखने गुढ़ियारी में लम्बी-लम्बी कतारें लगती थी। कभी कोई दुर्घटना ना हो जाये इसलिये बाद में प्रशासन ने इसे बंद करा दिया।

क्रेन वाले गणेश जी

जब बड़ी मूर्ति रखने का चलन शुरू हुआ तो गोल बाजार में इतनी बड़ी मूर्ति बनवा लिये कि उसे स्थापित करने के लिये दो-दो क्रेन की सहायता लेनी पड़ी इसलिये इसका नाम पड़ गया क्रेन वाला गणेश।

विवादास्पद समिति

गोलबाजार में ही एक गणेश उत्सव के लिये चंदा लेने के दौरान बड़ा विवाद हो गया। इस समय आयोजकों ने अपने गणेश उत्सव समिति का नाम ही विवादास्पद गणेश उत्सव समिति रख लिया।

खंडपीठ गणेश

कंकालीपारा में तम्बोली परिवार और अन्य लोगों ने बहुत ही आकर्षक प्रतिमा बनवा कर स्थापित किया जो काफी चर्चित रहता था। उन्ही दिनों रायपुर में खंडपीठ स्थापना को लेकर बहुत बड़ा आन्दोलन शुरू हुआ था। समिति वालों ने निर्णय लिया कि जब तक खंडपीठ की मांग पूरी नहीं होती तब तक गणेश विसर्जन नहीं करेंगे। इस तरह गणेशपक्ष समाप्त हो जाने के बाद भी यहां गणेश जी स्थापित रहे। इसी कारण कई वर्षों तक यहां स्थापित गणेश को खंडपीठ गणेश कहा कहते थे।

नारियल का गणेश

गुढियारी में परस पेंटर ने वहां की समिति के लिये कई नारियलों से विशाल गणेश जी की प्रतिमा बना दिया। इस गणेश प्रतिमा ने रायपुर के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। इस गणेश को देखने रायपुर ही नहीं, दूर-दूर से लोग आने लगे और गुढ़ियारी जो तब तक थोक किराना व्यवसाय के लिये जाना जाता था अब नारियल वाले गणेश के लिये भी प्रसिद्ध हो गया ।

बैलगाड़ी में गणेश झांकी

आईये अब गणेश विसर्जन की बात करें। बताते हैं पहले गणेश प्रतिमा का विसर्जन पुरानी बस्ती के प्राचीन खो-खो तालाब में किया जाता था. बैलगाड़ी में केले के पत्तों से सजा कर, झांकी निकाली जाती थी। चूँकि उस समय आज की तरह लाईट्स की व्यवस्था नहीं थी इसलिये बैलगाड़ी के आगे-आगे लोग मशालें लेकर चलते थे और इस तरह गणेश विसर्जन झांकी निकलती थी। बाद में कई वर्षों तक बूढ़ातालाब में मूर्ति विसर्जित होती रही। जब यहां का पानी गंदा होने लगा तो प्रशासन ने निर्णय लिया कि मूर्तियों का विसर्जन खारून नदी में किया जायेगा । कुछ साल खारून नदी में पुल के उपर से गणेश मूर्तियों को ढकेल कर विसर्जित किया जाता था। बाद में यहां भी फिसलने वाली मशीन बनायी गयी। कहतें हैं यह सलाह बढ़ईपारा के रामनाराण ने ही प्रशासन को दी थी । जब नदी का पानी भी गंदा होने लगा तब अब यहां कुंड बना कर गणेश मूर्ति विसर्जित की जाती है।

तो संक्षिप्त में ये है रायपुर में गणेश उत्सव का इतिहास। वैसे तो और भी बहुत सारी जानकारी है लेकिन पोस्ट लम्बा होने से फेसबुक के मित्र पढ़ते नहीं इसलिये फिरहाल इतना ही।

हरियाणा में खुद को किंगमेकर बनाने की जुगत में दुष्यंत चौटाला

अनन्या मिश्रा

हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीतियों के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी को एक तरह से झटका लगा है। लेकिन जेजेपी और इनेलो दलित आधार वाले दलों के साथ मिलकर खुद को किंगमेकर साबित करने की जुगत में जुटी है। बता दें कि जेजेपी इस चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज

पार्टी के साथ मिलकर मैदान में उतरी है। बता दें कि हाल ही में जननायक जनता पार्टी के 10 में से 6 विधायकों ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेजेपी के आधे से ज्यादा विधायक पार्टी में शामिल नहीं हैं। ऐसे में जेजेपी समेत अन्य राजनीतिक दल अपना जनाधार बढ़ाने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। हालांकि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी किंगमेकर बनकर उभरी थी। उस दौरान जेजेपी ने पिछली सरकार को अपना समर्थन दिया था, जिसके बदले में उनको डिप्टी सीएम सहित दो मंत्री पद मिले। वहीं गठबंधन टूटने के बाद दुष्यंत चौटाला की पार्टी कई मोर्चों पर चुनौतियों से जूझ रही है। वहीं पार्टी के विधायक मुखर होकर खुलेआम दुष्यंत की पार्टी और नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। बता दें कि पार्टी के कई विधायकों ने यह कहते हुए जेजेपी से पल्ला झाड़ लिया कि वह दूसरी पार्टी की नीतियों से अधिक प्रभावित हैं। बता दें कि इस साल अप्रैल महीने में जेजेपी को एक बड़ा झटका लगा था, जब राज्य इकाई के अध्यक्ष निशान सिंह ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीट पर जेजेपी ने चुनाव लड़ा था। लेकिन पार्टी को बमुश्किल 0.87 फीसदी वोट मिले थे। साथ ही पार्टी के सभी उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई थी। चुनाव नतीजों के बाद पार्टी की सभी जिला इकाइंयां भंग कर दी गईं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दुष्यंत चौटाला इस बार के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर अपनी पार्टी को मजबूती से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जेजेपी नेतृत्व सक्रिय रूप से राज्य का दौरान करने के साथ कैडर के मनोबल को बढ़ाने की कोशिश करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं।

ऊर्जा स्वालंबन की दिशा में सार्थक कदम है सूर्य घर योजना

विकास शर्मा

हाल के दिनों के तीन समाचारों ने मेरा ध्यान खींचा और इसमें मुझे भविष्य की तैयारी का खाका नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंत्रीमंडल ने ई- ड्राइव योजना को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत बिजली चलित वाहनों (इलेक्ट्रिक व्हीकल) को बढ़ावा देने के लिए अनुदान तथा 88 हजार 500 ई- चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2030 तक भारत में नवीकरणीय ऊर्जा से 500 गीगावॉट बिजली उत्पादन की तैयारी है। वहीं दिल्ली में आयोजित आटोमोटिव मैन्यूफैक्चरर्स एसोशिएशन के कार्यक्रम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दो वर्षों में पेट्रोल डीजल कारों के समान ही बिजली चलित वाहनों की कीमतें होंगी। इन तीनों समाचारों से विद्युत ऊर्जा और विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती जरूरत और महत्व को समझा जा सकता है। भारत में विगत एक दशक में जिस प्रकार से नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में संकल्पबद्ध प्रयास नजर आ रहा है यह दर्शाता है कि यह तैयारी आने वाले तीन-चार दशकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की जा रही है। पर्यावरण संतुलन तथा शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने परिणाम केंद्रित प्रयासों को बढ़ावा दिया है। वर्ष 2030 तक कुल ऊर्जा उत्पादन में जीवाश्म ईंधन (कोल, गैस, डीजल तथा लिग्नाईट) की भागीदारी को वर्तमान 54.5 प्रतिशत से घटाकर 32 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।

भारत की भौगोलिक स्थिति में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में अपार संभावना को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने आमजन को भी ऊर्जा उत्पादक बनाने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इस कड़ी में एक बहुत ही लोकप्रिय योजना है। योजना के तहत अगले कुछ वर्षों में 30 गीगावॉट (30 हजार मेगावॉट) बिजली देश के आम लोगों के घरों की छतों पर लगे सौर पैनलों से उत्पादित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह महत्वाकांक्षी योजना भावी जरूरतों की पूर्ति में आमजन की भागीदारी को बढ़ाने वाला है। दूरगामी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना पर 75 हजार 21 करोड़ रूपए व्यय किया जा रहा है।

इसमें भारी भरकम अनुदान के साथ ही आवश्यक विद्युत अधोसंरचना का विकास भी शामिल है। योजना के तहत देश के एक करोड़ घरों की छतों पर एक से तीन किलोवॉट के सौर पैनल स्थापित होंगे जो लघु बिजली संयंत्र की भांति कार्य करेंगे। अनुमान है कि तीन सौ यूनिट प्रतिमाह तक बिजली मुफ्त प्राप्त करने के साथ ही हितग्राही अपनी उत्पादित शेष बिजली को ग्रीड के माध्यम से राज्य बिजली कंपनियों को बेच सकेंगे। योजना की प्रारंभिक सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 13 फरवरी 2024 को शुरू होने के छह माह के अंदर एक करोड़ 28 लाख से अधिक हितग्राहियों ने सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए पंजीयन कराया है।

योजना हरित ऊर्जा उत्पादन के साथ ही रोजगार सृजन की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। इससे सौर ऊर्जा उपकरणों के निर्माण, परिवहन, आपूर्ति समेत संचारण और संधारण से जुड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के 17 लाख नए अवसर सृजित होने का अनुमान है। ऊर्जा पर खर्च कम होने से घरेलू बचत बढ़ने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में आम आम नागरिक की अप्रत्यक्ष भागिदारी भी सुनिश्चित हो सकेगी।

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की तात्कालिकता तथा इसके पीछे की दूरदर्शिता को भी समझा जा सकता है। देश की प्रगति और समृद्धि को समझने के लिए प्रति व्यक्ति आय की तरह प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत भी एक आधार है। साल 1947 में खपत 18.47 किलोवॉट ऑवर (केव्हीएच) से आज 2024 में 72 गुणा अधिक 1327 केव्हीएच पहुँच चुका है जिसके तेजी से बढ़ते हुए अगले 5-6 वर्षों में 1500 केव्हीएच तथा वर्ष 2050 में 2500 केव्हीएच प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष ऊर्जा खपत होने का अनुमान है। हमारी ऊर्जा जरूरतें कोयला आधारित संयंत्रों से उत्पादित बिजली पर अधिक निर्भर हैं जिसे समयबद्ध ढंग से नवीकरणीय ऊर्जा तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा श्रोतों से पूरा करने की आवश्यकता है। भारत में आज विद्युत उत्पादन क्षमता 446 गी. वॉ. है जिसमें 45.5 प्रतिशत गैर- जीवाश्म इंधन (नवीकरणीय ऊर्जा) से उत्पादित होता है। अब आगामी पाँच वर्षों में इसे बढ़ाकर 65 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता जो वर्तमान में 203 गीगावॉट है को अगले पाँच वर्षों में 500 गी. वॉ. तक ले जाने के लिए प्रयासरत है। इसमें पवन ऊर्जा की वर्तमान क्षमता को 46.6 गी. वॉ. से 140 गी. वॉ. और वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा से ऊत्पादित बिजली को 85.5 गी. वॉ. से 270 गी. वॉ. करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिस प्रकार से देश ने सिर्फ दस वर्षों में सौर ऊर्जा क्षमता को 2.82 गी. वॉ से बढ़ाकर 85.5 गी. वॉ. तक पहुंचाया है ऐसे में अगले पाँच वर्ष का लक्ष्य असंभव नहीं कहा जा सकता है।

भारत के संदर्भ में गैर जीवाश्म इंधन को मुख्य ऊर्जा श्रोत बनाने की जरूत इसलिए भी है क्योंकि जीवाश्म इंधन कई पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकी असंतुलन (इकोलॉजिकल इंबैलेंस) का कारण बन रहा है और बढ़ती ऊर्जी जरूरतों के साथ इसके खतरे और चिंताजनक हो जाएंगे। नवीकरणीय ऊर्जा समय की मांग और मानवता के लिए आवश्यक है। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की दिशा में जो कदम उठाए हैं उसके अच्छे परिणाम भी हमारे सामने है। इसके साथ ही वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 2005 की स्थिति सि 45 प्रतिशत तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास और बाद में एक आयाम और जोड़ा सबका प्रयास। विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में जनप्रयास को बढ़ावा देने की योजना है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ऊर्जा से उन्नति को गति मिलती है और जिस प्रकार सूर्य घर योजना को बहुआयामी बनाया गया है आशा की जा सकती है कि इस योजना से ऊर्जा आत्मनिर्भरता के साथ ही देश विकास की डगर पर निर्बाध आगे बढ़ सकेगा।

अमेरिका में राहुल गांधी के बयानों के मायने

प्रो सतीश कुमार

लोकतंत्र में प्रतिपक्ष के नेता की अहम भूमिका होती है। अगर वह विदेश के दौरे पर हो, तो उस देश के साथ स्थापित संवाद की अहमियत को नाकारा नहीं जा सकता। इसलिए राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा को विदेश नीति के आईने से समझना जरूरी है। यात्रा के लिए अमेरिका को पहले चुनना शायद उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक पसंद हो सकती है। अन्य कारण भी हो सकते हैं। यहां महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने किससे मुलाकात की और क्या कहा। वे कई सांसदों से मिले, जिनमें इल्हान ओमर भी थीं। इल्हान की पहचान इसलिए भी है कि वे घोर भारत विरोधी है और पाकिस्तान की तरफदारी करती हैं। कश्मीर पर उनके बयान देखे जा सकते हैं। विवाद का कारण मुलाकात तक सीमित होता, तो बात कुछ और होती।

राहुल गांधी ने दो अलग-अलग विश्वविद्यालयों में अपने संबोधन में सिख समुदाय का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में उनकी धार्मिक आजादी छीनी जा रही है और राज्यों के बीच मतभेद पैदा किया जा रहा है यानी संघवाद की बुनियाद तोड़ी जा रही है। धार्मिक उन्माद को हवा देने की कोशिश की जा रही है, भाषा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में तानाशाही चल रही है। ये सब बातें राहुल गांधी और अन्य नेता भारत में भी कहते रहे हैं। ऐसी बातों के लिए मीडिया में राहुल गांधी की खूब प्रशंसा भी हुई थी, लेकिन यहां विदेशी धरती का मामला था। सवाल किसी दल नहीं, बल्कि देश का था।

इसलिए इस यात्रा के असर की चर्चा जरूरी है। क्या यह अनायास ही हुआ है या इसके पीछे कोई राजनीतिक हित या शक्ति है? क्या भारत की बेहतर छवि बनाने का काम केवल सत्ता पक्ष का है या अन्य दलों की भी भूमिका होनी चाहिए? क्या लोकतंत्र की तराजू पर अमेरिकी सिक्का इतना खरा है कि उसका अनुसरण भारत में एक कार्बन कॉपी के रूप में किया जाना चाहिए? राहुल गांधी ने बांग्लादेश और

पाकिस्तान के संदर्भ में बहुत बातें नहीं कीं और यह भी कहा कि वे इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं। उन्होंने बांग्लादेश में हुए तख्तापलट में अमेरिका की भूमिका की चर्चा नहीं की।

चीन के संदर्भ में उन्होंने भारत की भूमि पर कब्जा करने और आक्रामक रुख की बात कही। यह भी माना कि चीन को ठिकाने लगाने में भारत और अमेरिका का सहयोग मददगार होगा। अगर अमेरिकी विदेश नीति और शक्ति की चर्चा करें, तो उसमें सॉफ्ट पॉवर की बहुत अहम भूमिका है। भारत के संदर्भ में केवल थिंक टैंक की चर्चा जरूरी है। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल जाना-माना नाम है। दुनियाभर से लोग वहां से डिग्री लेने के लिए लालायित रहते हैं। वहां भारत से संबंधित विषयों की पढ़ाई भी होती है। सैकड़ों की संख्या में हर वर्ष फेलोशिप दिये जाते हैं, जिनसे ऐसे शोधों की शुरुआत होती है, जिनमें यह स्थापित करने की कोशिश होती है कि भारत खंडहर में तब्दील हो रहा है।

पचास के दशक में भारत मदारियों और भिखारियों का देश था, पर 1990 के बाद भारत की तस्वीर एक कंप्यूटरयुक्त गुणवान देश में बदल गयी। विदेशी, विशेषकर अमेरिकी, थिंक टैंकों को यह बात चुभने लगी। उन्होंने पैंतरा बदला और भारत की जाति व्यवस्था को अमेरिका के रंगभेद से जोड़ दिया। सांप्रदायिकता की नयी परिभाषा दे दी। कई भारतीय विद्वान भी हैं, जो फेलोशिप के जरिये अमेरिका में रच-बस गये। उनके लेखों और किताबों से भारत में नैरेटिव बनाया जाता है और फिर उसे राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे विद्वानों की लंबी सूची है, जिसकी महीन व्याख्या राजीव मल्होत्रा ने अपनी नयी पुस्तक 'स्नैक्स इन गांगेस' में की है।

क्या अमेरिका लोकतंत्र का मसीहा है? साल 2021 और 2023 में अमेरिका ने लोकतंत्र पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पाकिस्तान को बुलाया गया, लेकिन बांग्लादेश को नहीं। जब दो साल पहले कर्नाटक में हिजाब विवाद उठा, तो अमेरिकी थिंक टैंकों में खूब चर्चा हुई, पर वही जब फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और अन्य यूरोपीय देशों में हुआ, तो अमेरिका चुप रहा। ऐसे कई उदाहरण हैं। भारत के अंदरूनी मसलों पर अमेरिकी व्यवस्था आग उगलती है, उसकी जलन भारत में महसूस होती है, क्योंकि पूरा इको तंत्र स्थापित है। पाठ्य पुस्तक तक उसकी भरपूर हिमायत करते हैं। तकनीक के जमाने में बात सीमेंट की तरह जम जाती है।

तीसरा सबसे अहम प्रश्न है कि क्या भारत की अंदरूनी समस्या का हल बाहरी व्याख्या से हो सकती है या देश के भीतर के विमर्श से। भारतीय लोकतंत्र में कई बीमारियां है, इससे किसी को इंकार नहीं है। समाज जाति में बंटा हुआ है और सांप्रदायिकता का खतरा भी है। गरीबी और अमीरी की खाई भी बढ़ती जा रही है, लेकिन ये तमाम खामियां अमेरिकी समाज में भी है। भारत के साथ एक बौद्धिक लड़ाई दशकों से चल रही है, जिसका केंद्र अमेरिका और यूरोप के देश हैं। चूंकि भारतीय मानस में आज भी घुन लगा हुआ और एक ग्रंथि पल रही है कि अंग्रेजी भाषा में, वह भी अमेरिकी तंत्र से, लिखी गयी बात सच ही होती है। इस ग्रंथि को तोड़ना जरूरी है। इस दिशा में पिछले कुछ वर्षों में कोशिश हुई है, पर औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के लिए बहुत कुछ होना बाकी है।

मोदी सरकार का संकल्प है विकसित भारत

अन्नपूर्णा देवी

लगभग सौ दिन पूर्व संपन्न लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए पर जनता ने लगातार तीसरी बार भरोसा जताया। यह जीत दरअसल मोदी सरकार द्वारा विगत एक दशक में किये गये कार्यों पर जनता की संतुष्टि की मुहर थी। यदि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के पिछले एक दशक के कार्यों का आकलन किया जाए, तो सरकार की अनेकानेक उपलब्धियां रही हैं। फिर भी, मेरी दृष्टि में कुछ कार्य ऐसे हुए हैं, जिन्हें भविष्य के इतिहासकार स्वर्णाक्षरों में अंकित करेंगे। बीते एक दशक में मोदी सरकार ने जनहित में ऐसे कई फैसले लिये, जो अभूतपूर्व हैं। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के द्वारा अप्रत्यक्ष कराधान में सुधार तथा तीन तलाक निरोधी कानून के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को गरिमामयी जीवन प्रदान करने से लेकर संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करना आदि जैसे अनेक फैसले न सिर्फ वर्तमान, बल्कि भविष्य के भारत की भी आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक रूपरेखा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। मोदी सरकार ने विगत एक दशक में उस मिथक को तोड़ा है, जिसमें यह माना जाता था कि सरकार की विकास एवं कल्याण योजनाएं लक्षित समूहों तक नहीं पहुंच पातीं। देश में हर परिवार को आवास मुहैया कराने के उद्देश्य से चलायी जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज 2 l45 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान देने से लेकर 11 करोड़ शौचालयों के निर्माण और किसान सम्मान निधि के तहत देश के लगभग 12 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता राशि देने तक सरकार की अनेक योजनाएं सफलतापूर्वक लक्षित समूहों तक पहुंच रही हैं, वह भी बिना किसी रिसाव के, नियमित रूप से, पूरे का पूरा सौ प्रतिशत। वैसे एक महिला होने के नाते मुझे विगत 10 वर्षों का समय तो 'महिलाओं को समर्पित मोदी कार्यकाल' के रूप में दिखाई देता है। वर्ष 2014 में सरकार गठन के कुछ समय पश्चात ही 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना से कन्या-महिला कल्याण की दिशा में जो यात्रा शुरू हुई, वह आज भी अनवरत जारी है। 'उज्ज्वला' योजना के तहत महिलाओं को धुएं से बचाना हो, या फिर 'जन-धन योजना' के तहत 25 करोड़ से अधिक महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना हो, विगत 10 वर्षों में सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में अनेक ठोस प्रयास किये हैं। महिलाओं के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता की मिसाल है कि 2013-14 में जेंडर बजट जहां लगभग 97 करोड़ रुपये था, वहीं 2024 के बजट में 237 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए तीन लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा कर दिया गया है। इसी तरह, मोदी सरकार द्वारा छोटे व्यवसायियों की मदद के लिए शुरू की गयी मुद्रा ऋण योजना में महिलाओं की भागीदारी 68 प्रतिशत है। अब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हमारे सामने है। इसके अलावा, स्टैंड अप इंडिया के तहत खास तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसके तहत अब तक 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किये जा चुके हैं। 'मिशन शक्ति', 'सेल्फी विद डॉटर' और 'सुकन्या समृद्धि योजना' जैसी योजनाओं ने हमारी बालिकाओं और युवतियों के लिए नया आसमान खोला है। मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन कर महिला कर्मी को मिलने वाले मातृत्व अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। यही नहीं, वर्षों से लंबित लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को पारित कर मोदी सरकार ने महिलाओं का अभूतपूर्व राजनीतिक सशक्तीकरण किया है। यह एक ऐतिहासिक महत्व का कदम है। आज का भारत 'महिला नेतृत्व में विकास' की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। सरकार के इन प्रभावकारी उपायों से देश में महिलाएं अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर हुई हैं। विधिशास्त्र की एक सूक्ति है कि 'न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए'। इसी तरह, विकास भी सिर्फ कागजी आंकड़ों में नहीं, बल्कि धरातल पर भी दिखना चाहिए। 'पीएम गतिशक्ति' व 'सागरमाला' जैसी अम्ब्रेला योजनाओं के तहत सरकार ने विगत दस वर्षों में जिस प्रकार रेलवे, सड़क, हवाई अड्डे और बंदरगाह के रूप में नयी पीढ़ी की आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया है, उसके बड़े दूरगामी परिणाम रोजगार और आर्थिक विकास के स्तर पर होने वाले हैं। वैश्विक स्तर पर भी भारत की एक नयी छवि गढ़ने के लिए मोदी सरकार को याद किया जायेगा। केंद्र सरकार की नीतियों ने भारत को आज दुनिया के अग्रणी देशों में लाकर खड़ा कर दिया है।

आम तौर पर विद्यार्थी इंजीनियरिंग की कॉमन ब्रांचेज को ही चुनते हैं लेकिन यह फील्ड इतनी विस्तृत है कि इसकी हर ब्रांच में आगे बढ़ने और बेहतर करियर बनाने का स्कोप है। इंजीनियरिंग की ऐसी ही एक ब्रांच है, रबर टेक्नोलॉजी। इसमें नेचुरल रबर, लेटेक्स और सिंथेटिक रबर से उपयोगी उत्पाद बनाए जाते हैं। अगर आप भी इंजीनियरिंग में कुछ अलग करने की सोच रहे हैं, तो रबर टेक्नोलॉजी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है।

बेहतर करियर बनाने का स्कोप है
रबर टेक्नोलॉजी

किसी रबर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले आपने शायद ही सोचा होगा कि यह फील्ड इंजीनियरिंग की उन चुनिंदा ब्रांचेज में से एक है, जिन्हें इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का भविष्य माना जाता है। गार्मेंट्स से लेकर टॉयज तक और फुटवियर से लेकर स्टेशनरी व एक्सेसरी तक आज हर चीज में रबर का इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि इस ब्रांच का स्कोप भी बहुत ज्यादा है। अगर आप भी इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं, तो रबर टेक्नोलॉजी में बढ़िया करियर बना सकते हैं।

क्या है रबर टेक्नोलॉजी?

रबर टेक्नोलॉजी विज्ञान की एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, जिसमें रबर के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ-साथ इलास्टोमर्स को उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। इसमें नेचुरल रबर, लेटेक्स और सिंथेटिक रबर की प्रोसेसिंग की जाती है और उनसे अलग-अलग उत्पाद बनाए जाते हैं। इस फील्ड को पॉलिमर टेक्नोलॉजी के लिए भी स्पेशलाइज्ड ब्रांच माना जाता है।

कौन-से कोर्स?

इस फील्ड में करियर प्लान करने के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जैसे विषय होने जरूरी हैं। इसके बाद आप बीटेक या बीई इन रबर टेक्नोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रबर टेक्नोलॉजी, एमटेक या एमई इन रबर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन रबर टेक्नोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मॉलिक्यूलर साइंस एंड रबर टेक्नोलॉजी जैसे कोर्स कर सकते हैं।

कैसी है वर्क प्रोफाइल?

आप इस फील्ड से जुड़ी कंपनीज में इन पदों पर काम कर सकते हैं -

टेस्टिंग टेक्नोलॉजिस्ट या टेक्नीशियन - ये सिस्टम को एनालाइज करते हैं और प्रोडक्शन टेस्ट्स की मदद से यह देखते हैं कि इक्विपमेंट्स क्वॉलिटी कंट्रोल एरेना के हिसाब से ठीक काम कर रहे हैं या नहीं।

प्रोडक्शन इंजीनियर्स - इनका बेसिक काम प्रोडक्शन, प्रोडक्ट क्वॉलिटी, क्वॉन्टिटी, स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ ऑपरेशन और मेंटेनेंस का खयाल रखना होता है।

पॉलिमर स्पेशलिस्ट्स - इनका काम मटेरियल के गुणों और बनावट की डीटेल्स जानने के लिए रिसर्च करना है ताकि इसका इस्तेमाल नए प्रोडक्ट बनाने में किया जा सके।

मटेरियल टेक्नोलॉजिस्ट्स - ये वेयरहाउसिंग गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे शिपिंग एंड रिसीविंग, सामान के परिवहन का मैनेजमेंट आदि।

भविष्य की संभावनाएं

आप रबर इंडस्ट्री के साथ-साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी जॉब कर सकते हैं। इस फील्ड में सरकारी संस्थानों में भी काम करने के अवसर हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड रबर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को हायर करती है। इस फील्ड में विदेशों में जाकर रिसर्च करने का भी बहुत स्कोप है।

जरूरी स्किल्स

यह फील्ड उन लोगों के लिए है, जिन्हें टेक्नोलॉजी के साथ-साथ उन प्रणालियों में भी रुचि हो, जिनसे रबर की प्रोसेसिंग की जाती है। आपको मेन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आपमें बेहतरीन लीडरशिप क्वॉलिटी, आत्मविश्वास, परिश्रमी रवैया और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी जरूरी है।

सैलरी कितनी?

इस फील्ड में शुरुआत 15 से 20 हजार रुपए की सैलरी से होती है। अनुभव प्राप्त करने के बाद आपका वार्षिक पैकेज 5-7 लाख रुपए के बीच होगा।

प्रमुख संस्थान

- गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, गांधीनगर
- इंडियन रबर इंस्टीट्यूट, कोलकाता
- हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चेन्नई
- आईआईटी, खड़गपुर
- कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केरल
- रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, केरल
- मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चेन्नई
- यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोलकाता
- हरिशंकर सिंघानिया इलास्टोमर एंड टायर रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजस्थान

क्या आप प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं

आज बारहवीं के बाद ही युवा कॅरियर निर्धारित करने लगे हैं। आज से कुछ सालों पहले तक यही सोच थी कि पहले पढ़ाई पूरी कर लें, बाद में नौकरी के बारे में सोचेंगे। अधिकतर स्टूडेंट्स यह सोचते हैं कि यदि परंपरागत प्रोफेशनल कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए, सीएस आदि में एडमिशन नहीं मिल पाया तो उसके बाद प्रोफेशनल और एकेडमिक कोर्स में से क्या बेहतर होगा।

पहले ये सोचें

प्रोफेशनल कोर्स में जाने से पहले आपको कुछ सवालों के जवाब खुद तलाशने होंगे। क्या आपको अपनी परिस्थितियों और पारिवारिक समस्याओं के चलते जॉब की सख्त आवश्यकता है? क्या आपका परिवार आर्थिक रूप से इतना सक्षम है कि प्रोफेशनल शिक्षा के खर्च का वहन कर सके? अधिकतर स्टूडेंट्स पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं के चलते प्रोफेशनल कोर्स का चयन करते हैं, ताकि कुछ वर्षों की पढ़ाई करने के बाद नौकरी का बेहतर विकल्प मिल सके। लेकिन कुछ कोर्स की फीस काफी अधिक होती है। इस कारण आपके लिए बेहतर होगा कि कोर्स चुनने से पहले उसकी फीस, कैंपस प्लेसमेंट और घर की आर्थिक स्थिति से भलीभांति अवगत हो जाएं।

क्या है रूचि

कोई भी कोर्स खराब नहीं होता है, क्योंकि सभी क्षेत्रों में सभी तरह के लोगों की मांग रहती है। इस कारण सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि हमें यह कोर्स करना है। कोर्स का चयन करते समय कुछ बातों को ध्यान रखेंगे, तो आप सही और बेहतर कोर्स चुनने में सफल हो सकते हैं। सही कॅरियर चुनने से पहले आप अपनी रुचि, आर्थिक स्थिति और आनेवाले समय में इनकी मांगों को अवश्य देखें। अब कॉरियर के क्षेत्र में मिलने वाले अवसरों का वर्गीकरण कुछ इस तरह से हो गया है कि हर किसी के पास अपनी क्षमताओं, रुचियों व रुझानों के मुताबिक कई तरह के कॉरियर ऑप्शन हैं। प्रोफेशनल कोर्स ने छात्रों को ढेरों विकल्प दिए हैं।

पढ़ाई पहले

अक्सर स्टूडेंट्स किसी संस्थान में इस कारण एडमिशन ले लेते हैं कि उसका नाम काफी है। अन्य संस्थानों की अपेक्षा कहीं ज्यादा पैसे भी देने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पछतावा तब होता है, जब उस संस्थान में अपेक्षा के अनुरूप पढ़ाई नहीं होती है। उस समय स्टूडेंट्स के पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। आप यदि किसी संस्थान में किसी तरह का कोर्स करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस संस्थान के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। जानकारी प्राप्त करने का बेहतर तरीका यह है कि आप उस संस्थान में पढ़ रहे स्टूडेंट्स से पढ़ाई और फैकल्टी मेंबर्स के बारे में सही जानकारी लें। वहां के स्टूडेंट्स आपको सही बात बता देंगे। कुछ स्टूडेंट्स संस्थान के प्रोस्पेक्टस के आधार पर ही कैंपस प्लेसमेंट को सही मान लेते हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि आप पिछले वर्ष पास किए गए स्टूडेंट्स की संख्या और नौकरी प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स को देखकर ही कोई निर्णय लें।

अगर आप खुद को काबिल समझते हैं, तो आगे बढ़कर इसका नमूना भी पेश करें। यह न सोचें कि आपकी काबिलियत के बारे में मैनेजमेंट को सपना आएगा और वह चलकर आपके पास आएगा।

जॉब के दौरान करना ही पड़ेगा चुनौतियों का सामना

अनिकेत सक्सेना एक प्रतिष्ठित संस्थान में जिम्मेदार पद पर काम करता है। उसे संबंधित इंडस्ट्री में काम करते हुए दो दशक से ऊपर हो चुके हैं। इस दौरान एक- दो बार उसे पिंक स्लिप भी थमा दी गई। इससे उसे झटका तो लगा, पर उसने इसके पीछे के कारणों को जानने-समझने और उन्हें दूर करने की कभी परवाह नहीं की। एक बार नौकरी मिलने के बाद वह बस, मशीन की तरह काम करता जाता था। माना कि वह विनम्र और अनुशासित रहा है पर वह जिस तरह के पेशे में है, उसमें शायद ही वह कभी इनोवेटिव आइडियाज की पहल करता है। जबकि उसके प्रोफेशन में यह सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वर्तमान संस्थान में नौकरी उसे काफी मशक्कत के बाद मिली, लेकिन यहां भी उसने खुद को साबित करने और अलग पहचान बनाने की दिशा में कोई खास प्रयास नहीं किया। यहां भी उसके सामने कई बार मुश्किलें आईं, पर उसने इन्हें समझने और खुद को सुधारने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि उसे लगता है कि वह बहुत काबिल है और इसके लिए उसे तरक्की भी मिलनी चाहिए, पर अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए वह कभी टीम लीडर के रोल में आने की पहल नहीं करता। ऐसे में उसके सामने बार-बार मुश्किल आती है, पर वह कभी भी हकीकत को समझने के लिए तैयार नहीं होता।

अगर आपके साथ भी यही स्थिति है, तो समय रहते खुद को सुधार लें। इस मुगालते में न रहें कि आप बहुत प्रतिभावान हैं, बस बाकी लोग या मैनेजमेंट इसे समझना नहीं चाहते। अगर आप खुद को काबिल समझते हैं, तो आगे बढ़कर इसका नमूना भी पेश करें। यह न सोचें कि आपकी काबिलियत के बारे में मैनेजमेंट को सपना आएगा और वह चलकर आपके पास आएगा।

पहल के लिए रहें तत्पर

आज के समय में किसी भी संस्थान में मैनेजमेंट की निगाह में आप तभी आ सकते हैं, जब आप खुद को लीडर की भूमिका में पेश करेंगे। इसके लिए आपको खुद को सक्रिय भूमिका में लाना होगा। अगर आप मशीन की तरह काम में जुटे रहते हैं और अपनी तरफ से कोई नई पहल नहीं करते या अपनी टीम या विभाग के सदस्यों को उत्साहित नहीं कर पाते, तो आप इस भूमिका में नहीं आ सकते।

जगाएं आत्मविश्वास

टीम लीडर बनकर प्रमोशन और पहचान पाना चाहते हैं, तो खुद आगे बढ़कर नई चुनौतियों का सामना करने का साहस दिखाना होगा। इसके लिए सबसे पहले अपना आत्मविश्वास जगाना होगा और हर काम को पॉजिटिव नजरिए से पूरा करने के लिए दृढ़ता दिखानी होगी। कोई भी नया काम सामने आने पर अगर आप यह कहकर उसे करने से मना कर देंगे कि आपने तो कभी उस तरह का काम किया ही नहीं, तो यह आपके करियर के लिए नकारात्मक हो सकता है। इसके बजाय यह कहें कि यद्यपि मैंने यह काम नहीं किया है लेकिन मुझे मौका मिला, तो मैं इसे करने का पूरा प्रयास कर सकता हूं।

सीखें हर पल

आज के समय में आगे वही बढ़ता है, जो हर समय, हर किसी से कुछ-न-कुछ सीखने के लिए तत्पर रहता है। जिसने यह मान लिया कि वह तो सब कुछ जानता है, उसके लिए सीखने को कुछ बचा ही नहीं, उसके लिए तरक्की का रास्ता भी बंद हो जाता है। सब कुछ जानने की तसल्ली ही उसके आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध कर देती है। याद रखें, अगर आप अपने आंख, कान और दिमाग खुले रखेंगे, तो हमेशा कुछ-न-कुछ नया दिखेगा।

शिकायतों से बचें

कुछ लोगों को दूसरों से हमेशा शिकायतें रहती हैं। अपना काम अच्छी तरह से न कर पाने का ठीकरा भी वे दूसरों के सिर ही फोड़ना चाहते हैं। इससे बचकर रहें। ध्यान रखें, हमेशा आगे की ओर वही बढ़ता है, जो दूसरों को नहीं, खुद को देखता है। दूसरे क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, इस पर ध्यान देने के बजाय वह अपने काम को सही तरीके से करने का प्रयास करता है।

करें कुछ अलग

नौकरी के दौरान आठ घंटे का समय बिता देने से पहचान नहीं मिलती। पहचान मिलती है कुछ नया और इनोवेटिव करने से। अपने टैलेंट का विश्लेषण करें। इस बारे में सोचें कि आप क्या और कैसे नया कर सकते हैं। खुद को अपडेट करें, तराशें। अपने प्रोफेशन से जुड़ी नवीनतम चीजों के बारे में जानें। थोड़े दिन के अभ्यास के बाद आपको हर दिन कुछ नया लगने लगेगा। एक बार यह आदत बन जाने के बाद आपको नया और चुनौतीपूर्ण करने में आनंद महसूस होने लगेगा।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

राहुल विदेश में भारत को कर रहे बदनाम : रामदास अठावले

मुंबई। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी विदेश यात्राओं के दौरान भारत को बदनाम करने से रोकने के लिए उनका पासपोर्ट रद्द करने की मांग की। महाराष्ट्र के पालघर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) गांधी को आरक्षण विरोधी बयान देना शोभा नहीं देता। अठावले ने गांधी की हाल की अमेरिका यात्रा के दौरान की गई कुछ टिप्पणियों पर एक सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही। आपको बता दें कि राहुल के बयान के बाद बवाल शुरू हो गया था। अठावले ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी विदेश यात्रा करते हैं और ऐसे बयान देकर भारत को बदनाम करते हैं। उन्हें ऐसी टिप्पणी करने से रोकने के लिए उनका पासपोर्ट रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब वह कहते हैं कि वह देश में आरक्षण खत्म कर देंगे तो यह गंभीर है। राहुल गांधी के बयान से पिछड़ा समाज नाखुश है।

राहुल के खिलाफ बयान पर बवाल, कांग्रेस का प्रदर्शन

नईदिल्ली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर उनके बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया जो लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर उनके बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि हाल में अपने अमेरिका दौरे के दौरान राहुल ने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिससे सिसायी बवाल शुरू हो गया। पलटवार में भाजपा और एनडीए के नेताओं की ओर से भी बयान दिए है। कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि हम राहुल गांधी के रास्ते पर चलते हुए संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हम बीजेपी से नहीं डरते। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी के समर्थन में खड़ा है।

इस बार तेज प्रताप यादव भी आ गए ईडी के शिकंजे में

नईदिल्ली। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंक केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और दूसरे आरोपियों को इस मामले में आरोपी मानते हुए समन जारी कर दिया है। साथ ही इस बार लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी इस बार प्रवर्तन निदेशालय के लपेटे में आ गए हैं। कोर्ट ने अखिलेश्वर सिंह के साथ-साथ उनकी पत्नी किरण देवी को भी समन भेजा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। वह एके इंफोसिस लिमिटेड के निदेशक भी थे, इसीलिए उन्हें भी तलब किया गया है। उन्हें कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस केस में बीते 6 अगस्त को 11 लोगों के विरुद्ध पूरक चार्जशीट दायर की थी। हालांकि, इनमें से 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

आतिशी के माता-पिता के थे गिलानी से संबंध : स्वाति

नईदिल्ली। दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री आतिशी के माता-पिता पर अफ़ज़ल गुरु से संबंध होने का आरोप लगाने के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि आतिशी के माता-पिता के एसएआर गिलानी से घनिष्ठ संबंध थे, जो 2001 के संसद हमले के मामले में आरोपी था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। स्वाति ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आतिशी मर्लेना के माता पिता के एसएआर गिलानी के साथ गहरे संबंध थे। राज्यसभा सांसद ने कहा कि गिलानी पे आरोप थे कि संसद पे हमले में उनका भी हाथ था। 2016 में उन्होंने अफ़ज़ल गुरु की याद में दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम में आतिशी मर्लेना के माता पिता स्टेज पे गिलानी के साथ थे। इस प्रोग्राम में नारे लगाये गये थे - एक अफ़ज़ल मारोगे तो लाखों पैदा होंगे। कश्मीर माँगे आज़ादी।

आतिशी को लेकर भाजपा ने साधा केजरीवाल पर निशाना

नईदिल्ली। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो इस्तीफे का नाटक कर रहे हैं वह इस्तीफा नहीं है, यह नया पद है। उन्होंने कहा कि पहले वह जेल के अंदर से सीएम थे, फिर जमानत मिलने के बाद वह सीएम बने और अब वह प्रॉक्सी सीएम बनकर काम कराएंगे। आतिशी एक प्रॉक्सी सीएम हैं। उन्हें दिल्ली का मनमोहन सिंह बना दिया गया है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि चेहरा बदलने से क्या चरित्र बदल जाएगा? कांग्रेस भी कह रही है कि वे भ्रष्ट हैं, आज से दिल्ली में नया ड्रामा शुरू होगा, आप बंद करें ये ड्रामा। भाजपा नेता ने कहा कि आतिशी को सोचना चाहिए कि दिल्ली की जनता के लिए क्या काम करना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने मंगलवार को एक बयान जारी कर आतिशी को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले की आलोचना की।

जम्मू-कश्मीर में चुनाव को लेकर लोगों में दिखा उत्साह

■ मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें

जम्मू। जम्मू-कश्मीर में दस साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बुधवार को वोटिंग हुई। लोकतंत्र के इस महापर्व में सात जिलों की 24 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार सुबह सात बजे से वोटिंग शुरू हुई, शाम छह बजे तक मतदान हुआ। जिन मतदान केंद्रों पर आखिरी समय तक भी मतदाताओं की कतारें होंगी तो वहां मतदान समय अवधि बढ़ाने का प्रावधान रहेगा।

कश्मीर संभाग के 16 और जम्मू संभाग के 8 विधानसभा क्षेत्रों में 219 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 23.27 लाख मतदाता करेंगे। प्रदेश में 3276 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।

कश्मीर संभाग में अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम, जम्मू संभाग में डोडा, रामबन और किश्तवाड़ जिले में मतदान होगा। कश्मीर संभाग के पंपोर, त्राल, पुलवामा, राजपोरा, जैनापोरा, शोपियां, डीएच पोरा, कुलगाम, देवसर, डोरू, कोकरनाग (एसटी), अनंतनाग पश्चिम, अनंतनाग, श्रीगुफवारा-बिजबेहरा, शांगस-अनंतनाग पूर्व, पहलगाम और जम्मू संभाग में इंद्रवाल, किश्तवाड़, पाडर-नागसेनी, भद्रवाह, डोडा, डोडा पश्चिम, रामबन और बनिहाल में मतदान हो रहा है।

नवीनतम मतदाता सूची के तहत 23,27,580 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं, जिनमें 11,76,462 लाख पुरुष, 11,51,058 लाख महिला और 60 थर्ड जेंडर शामिल हैं। 5.66 लाख युवा मतदाता हैं। इसमें 18 से 29 वर्ष की आयु के बीच 5.66 लाख, 18 से 19 वर्ष की आयु के 1,23,960 लाख मतदाता शामिल हैं। इनमें से 10,261 पुरुष और 9,329 महिलाएं पहली बार मतदान करेंगे। इसी तरह 28,309 दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्यूडी) और 85 वर्ष से अधिक आयु के 15,774 मतदाता पात्र हैं।

अनंतनाग जिले में 64 उम्मीदवार, पुलवामा जिले में 45, डोडा जिले में 27, कुलगाम जिले में 25, किश्तवाड़ जिले में 22, शोपियां जिले में 21, रामबन जिले में 15, किश्तवाड़ जिले में 48, इंदरवाल विधानसभा क्षेत्र में 9, किश्तवाड़ विधानसभा क्षेत्र में 7, पाडर-नागसेनी विधानसभा क्षेत्र में 6, डोडा जिले में भद्रवाह विधानसभा क्षेत्र में 10, डोडा विधानसभा क्षेत्र में 9, डोडा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 8 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। रामबन जिले में रामबन विधानसभा क्षेत्र में 8, बनिहाल विधानसभा क्षेत्र में 7, पुलवामा जिले में पंपोर विधानसभा क्षेत्र में 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।

वहीं, त्राल विधानसभा क्षेत्र में 9, पुलवामा विधानसभा क्षेत्र में 12, राजपोरा विधानसभा क्षेत्र में 10, शोपियां जिले में जैनपोरा विधानसभा क्षेत्र में 10, शोपियां विधानसभा क्षेत्र में 11, कुलगाम जिले में डीएच पोरा विधानसभा क्षेत्र में 6, कुलगाम विधानसभा क्षेत्र में 10 और देवसर विधानसभा क्षेत्र में 9 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अनंतनाग जिले में डोरू विधानसभा क्षेत्र में 10, कोकरनाग (एसटी) विधानसभा क्षेत्र में 10, अनंतनाग पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 9, अनंतनाग विधानसभा क्षेत्र में 13, श्रीगुफवारा-बिजबिहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 3, शांगस-अनंतनाग पूर्व विधानसभा क्षेत्र में 13, पहलगाम विधानसभा क्षेत्र में 6 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।

डोडा जिले में तीन विधानसभा क्षेत्रों में कुल 3,10,613 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 1,60,057 पुरुष, 1,50,521 महिलाएं और 8 थर्ड जेंडर शामिल हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 534 मतदान केंद्र हैं।

अनंतनाग जिले में सात विधानसभा क्षेत्रों में 6,67,843 मतदाता हैं, जिनमें 3,36,200 पुरुष, 3,31,639 महिलाएं और 4 ट्रांसजेंडर हैं। जिले भर में 844 मतदान केंद्रों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

रामबन जिले में दो विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2,24,214 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 1,16,019 पुरुष मतदाता, 1,08,193 महिला मतदाता और 1 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। यहां कुल 365 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

शोपियां जिले को दो विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें कुल 2,09,062 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 1,04,894 पुरुष, 1,04,161 महिलाएं और 7 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में 251 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।

पुलवामा जिले में कुल 4,07,637 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें चार विधानसभा क्षेत्रों में 2,02,475 पुरुष, 2,05,141 महिलाएं और 21 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। जिले में 481 मतदान केंद्र बनाए हैं।

कुलगाम जिले में तीन विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 3,28,782 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 1,64,852 पुरुष, 1,63,917 महिला और 13 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। यहां 372 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।

तीन विधानसभा क्षेत्रों वाले किश्तवाड़ जिले में कुल 1,79,374 मतदाता हैं, जिनमें 91,935 पुरुष और 87,435 महिला और 4 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। जिले भर में 429 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। कुल 302 शहरी और 2974 ग्रामीण मतदान केंद्र हैं।

चुनाव में मुफ्त सुविधाओं का वादा रिश्वत देने जैसा

सुप्रीम कोर्ट जल्द करेगा याचिका पर सुनवाई

नई दिल्ली। चुनाव के दौरान मुफ्त रेवड़ी बांटने के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने अहम माना है और इस पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि याचिका सुनवाई के लिए लिस्टेड है और वे इसे सुनवाई से नहीं हटाएंगे। दरअसल वकील अश्विनी उपाध्याय ने चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों द्वारा मुफ्त सुविधाएं देने के वादे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यह याचिका लिस्टेड है, लेकिन अन्य मामले की सुनवाई की वजह से आज इस याचिका पर सुनवाई की उम्मीद कम ही है।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की सदस्यता वाली पीठ के समक्ष यह याचिका सूचीबद्ध है। याचिका दायर करने वाले वकील ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मांग की कि याचिका को सूचीबद्ध रखा जाए ताकि कल इस मामले पर सुनवाई हो सके। इस पर पीठ ने कहा कि यह मामला बेहद अहम है और वे याचिका को सूची से नहीं हटाएंगे।

उल्लेखनीय है कि याचिका में मांग की गई है कि राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में लोकलुभावन वादों पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि ये वादे राजनीतिक फायदे के लिए किए जाते हैं। याचिका के अनुसार, ऐसे वादे संविधान का उल्लंघन करते हैं और चुनाव आयोग को इनकी रोक के लिए कदम उठाने चाहिए। याचिका में अश्विनी उपाध्याय ने चुनाव आयोग को ऐसी राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिह्नों को फ्रीज करने और राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की मांग की है, जो लोगों को चुनाव के दौरान मुफ्त सुविधाएं देने का वादा करते हैं। याचिका में कहा गया है कि चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से तर्कहीन मुफ्त सुविधाएं देने का वादा मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करता है, इससे चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता भी दूषित होती है।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुफ्त उपहारों की पेशकश करके मतदाताओं को प्रभावित करने की राजनीतिक दलों की हालिया प्रवृत्ति न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है, बल्कि संविधान की भावना को भी चोट पहुँचाती है। यह अनैतिक व्यवहार सत्ता में बने रहने के लिए राजकोष की कीमत पर मतदाताओं को रिश्वत देने जैसा है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों और प्रथाओं को बनाए रखने के लिए इससे बचना चाहिए। अभी देश में आठ मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल और 56 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल हैं। देश में पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की कुल संख्या लगभग 2,800 है।

महिलाओं को हर माह दो हजार, गरीबों को सौ गज जमीन हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र

चंडीगढ़। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की गारंटी का एलान किया। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदय भान भी मौजूद थे। सात वादे, पक्के इरादे के तहत कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में सात बड़ी गारंटी दी हैं। कांग्रेस ने इस गारंटी के तहत राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण वादे किए हैं। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर हरियाणा के नागरिकों को बेहतर प्रशासन और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित करेगी और किसानों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाएगी।

कांग्रेस के वादे-

■ सभी महिलाओं (18-60 आयु) को 2000 रुपये प्रति माह ■ 500 रुपये में गैस सिलेंडर ■ बुजुर्गों, दिव्यांगों व विधवाओं को 6000 पेंशन ■ कर्मचारियों को ओपीएस ■ सरकारी विभागों में 2 लाख पक्की भर्तियां ■ हरियाणा को नशा मुक्त बनाएगी ■ तस्करों पर लगेगी नकेल ■ 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज (चिरंजीवी योजना) ■ 300 यूनिट मुफ्त बिजली ■ 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट व पक्का मकान देने की योजना ■ किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी ■ किसानों को तुरंत मुआवजे का प्रावधान ■ ओबीसी की क्रीमी लेयर सीमा बढ़ाकर 10 लाख ■ जातिगत सर्वे करवाया जाएगा।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच आज से

चेन्नई। भारत और बांग्लादेश के बीच गुरुवार से दो मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। पहला मुकाबला 19 सितंबर से चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। इसको लेकर दोनों टीमें तैयारी में जुटी हुई हैं। सीरीज शुरू होने से पहले मंगलवार को भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज यानी बुधवार को भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गंभीर ने संकेत दिए हैं कि ध्रुव जुरेल और सरफराज खान जैसे युवाओं को बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए चुने जाने की संभावना नहीं है। गंभीर ने मैच की पूर्व संध्या पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इन दोनों को टेस्ट टीम में खेलने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।

गंभीर ने स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर भी बातचीत की। गंभीर के मुताबिक बुमराह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं। गंभीर का मानना है कि भारत लंबे समय से बल्लेबाजों का दीवाना रहा है, लेकिन अब उन्हें खुशी है कि लोगों ने गेंदबाजों की भी तारीफ करनी शुरू कर दी है। इसके अलावा भी भारतीय टीम के मुख्य कोच ने कई मुद्दों पर बातचीत की। आइए जानते हैं...

भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि खेलने की सबसे अच्छी शैली वह शैली है जिससे टीम को जीतने में मदद मिलती है। गंभीर ने इससे स्पष्ट संकेत दिया है कि वह बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में वह खिलाड़ियों को अति आत्मविश्वास से बचाएंगे। बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को हराने के बाद आत्मविश्वास से भरी है और ऐसे में भारतीय खिलाड़ी उन्हें हल्के में लेने की कोशिश नहीं करेंगे।

भारत की संभावित प्लेइंग-11: रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

लाल निशान में बंद हुए सेंसेक्स-निफ्टी

नईदिल्ली। प्रमुख इक्विटी इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी आज यानी बुधवार को सुबह के सेशन में नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद गिरावट के साथ बंद हुए। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर फैसले से पहले निवेशकों ने मुनाफावसूली की और इससे आईटी शेयरों में गिरावट आई। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 131.43 अंक या 0.16% की गिरावट के साथ 82,948.23 पर बंद हुआ। इंट्रा डे में यह 246.72 अंक या 0.29 प्रतिशत चढ़कर 83,326.38 के लाइफ टाइम हाई लेवल पर पहुंचा था। एनएसई निफ्टी भी 41 अंक या 0.16% की गिरावट के साथ 25,377.55 पर बंद हुआ। इंट्रा डे में इसने 63.65 अंक या 0.25 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,482.20 के नए उच्चतम स्तर को छुआ। निफ्टी50 पर टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और विप्रो सहित 33 शेयर लाल निशान में बंद हुए जिनमें 3.50 प्रतिशत तक की गिरावट आई।

क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स घटकर शून्य

नई दिल्ली। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) को घटाकर प्रति टन शून्य कर दिया है। यह निर्णय 18 सितंबर से प्रभावी है। यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है और दो सप्ताह के अंतराल पर यानी हर पखवाड़े औसत तेल कीमतों के आधार पर इसकी समीक्षा की जाती है। इस तरह का आखिरी संशोधन 31 अगस्त को हुआ था, जब कच्चे पेट्रोलियम पर अप्रत्याशित कर 1,850 रुपये प्रति टन निर्धारित किया गया था। डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन या एटीएफ के निर्यात पर भी एसएईडी को शून्य पर बरकरार रखा गया है। मंगलवार को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि नई दरें 18 सितंबर से प्रभावी होंगी। भारत ने पहली बार 1 जुलाई 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर कर लगाया था।

मनबा फाइनेंस का आईपीओ 23 सितंबर को खुलेगा

नईदिल्ली। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) मनबा फाइनेंस लिमिटेड ने 151 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए 114-120 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी ने बुधवार को घोषणा की कि उसका आईपीओ 23 सितंबर को खुलेगा और 25 सितंबर को बंद होगा। मनबा फाइनेंस का आईपीओ पूर्णत: 1.26 करोड़ ताजा शेयर का इश्यू है। इसकी कीमत 151 करोड़ रुपये बैठती है। महाराष्ट्र स्थित मनबा फाइनेंस में प्रवर्तकों की वर्तमान में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कंपनी निर्गम से हासिल राशि का इस्तेमाल भावी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने, ऋण देने तथा सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए करेगी।

त्योहारी सीजन में काबू में रहेंगे खाद्य तेलों के दाम!

नईदिल्ली। सरकार ने हाल ही में खाद्य तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है लेकिन इसके बावजूद खाद्य तेल प्रोसेसर्स को रिटेल प्राइस बढ़ाने से रोकने की सलाह दी है। इसका कारण यह है कि कम शुल्क पर आयातित खाद्य तेलों का पर्याप्त स्टॉक अभी भी उपलब्ध है। 14 सितंबर 2024 से कच्चे सोयाबीन तेल, कच्चे पाम तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 20% कर दी गई है। इससे कच्चे तेलों पर प्रभावी शुल्क 27.5% हो गया है। रिफाइंड पाम तेल, रिफाइंड सूरजमुखी तेल और रिफाइंड सोयाबीन तेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 32.5% कर दिया गया है, जिससे रिफाइंड तेलों पर प्रभावी शुल्क 35.75% हो गया है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने खाद्य तेल संघों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की और कहा कि कम शुल्क पर आयातित खाद्य तेलों का स्टॉक 45 से 50 दिनों की घरेलू खपत के लिए पर्याप्त है।

पैरालंपिक में दिव्यांग खिलाड़ियों ने जीता देशवासियों का दिल

आदर्श प्रकाश सिंह

पेरिस पैरालंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने भारत का मस्तक ऊंचा कर दिया है। शारीरिक रूप से अक्षम इन खिलाड़ियों पर हमें गर्व होना चाहिए। उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करके उन्होंने कुल 29 पदक जीते हैं जिनमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में भारत 18वें स्थान पर रहा। यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तीन साल पहले टोक्यो में हम 24वें स्थान पर थे। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में मिले 19 पदकों का रिकॉर्ड भी इस बार ध्वस्त हो गया। पैरालंपिक में दिव्यांग खिलाड़ी या एथलीट हिस्सा लेते हैं। साधारण परिवार से आने वाले इन खिलाड़ियों के संघर्ष की कहानी सुन कर किसी की भी आंख नम हो जाएगी। किसी के दोनों हाथ नहीं है तो कोई एक कृत्रिम पैर लगा कर दौड़ रहा है। पेरिस पैरालंपिक में भारत की ओर से 84 खिलाड़ी भाग लेने गए थे। इसमें से 23 खिलाड़ी हरियाणा से थे। खेलों में हरियाणा हमेशा अग्रणी रहा है। मुक्केबाजी और कुश्ती में इस राज्य का दबदबा है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि वहां खेलों का बढ़िया ढांचा काम कर रहा है।

केन्द्र सरकार दिव्यांग खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित कर रही है। पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 75 लाख, रजत विजेता को 50 लाख और कांस्य पदक विजेता को 25 लाख रुपये दिए जाएंगे। पेरिस में महिला एथलीटों ने कमाल का प्रदर्शन किया है। भारत के 29 में से 10 पदक बेटियों के नाम रहे। भारत की ओर से इस बार महिलाओं का रिकॉर्ड प्रतिनिधित्व भी रहा। कुल 84 एथलीट के भारतीय दल में 32 महिलाएं थीं। पदक जीतने वाली 10 महिलाओं में तुलसिमति, शीतल देवी, मनीषा रामदास समेत सात एथलीट पहली बार पैरालंपिक में भाग लेने गई थीं।

टोक्यो में स्वर्ण जीतने वाली निशानेबाज अवनि लखेरा और भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने अपने खिताब बचाए हैं। इन दोनों ने पेरिस में भी स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। अवनि लगातार दो स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। राजस्थान की अवनि ने 11 साल की उम्र में कार दुर्घटना में अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। साथ ही कमर का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त होने से व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। इस हादसे से अवनि पूरी तरह टूट चुकी थी। मगर, पिता ने उसका हौसला बढ़ाया और आज वह दो स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी है। इसके अलावा भाला फेंक में सुमित अंतिल ने भी लगातार दूसरे पैरालंपिक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने तीन साल पहले टोक्यो में स्वर्ण जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से वादा किया था कि एक स्वर्ण और जीतूंगा। सुमित ने न केवल अपना वादा निभाया बल्कि पेरिस में जीता हुआ स्वर्ण पदक प्रधानमंत्री के नाम कर दिया।

भाला फेंक में बौने कद (चार फीट चार इंच) के नवदीप सिंह ने भी स्वर्ण पदक जीता है। वह भाला फेंक के एफ 41 वर्ग में देश के पहले चैम्पियन हैं। उनका कहना है, %हमें भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। मैंने भी देश का नाम रोशन किया है।% उन्हें अपने गांव में लोगों के तानों का भी सामना करना पड़ा। वह कहते हैं किसी को हमारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक मजेदार वाक्या तब हुआ जब प्रधानमंत्री को वह टोपी पहनाना चाहते थे। पीएम मोदी उनकी मजबूरी समझते हुए उनकी सुविधा के लिए फर्श पर बैठ गए। वह बाएं हाथ से थ्रो करते हैं। पानीपत के 23 वर्षीय नवदीप ने दस साल की उम्र में अपनी एथलेटिक यात्रा शुरू की। नीरज चोपड़ा से उन्हें काफी प्रेरणा मिलती है। टोक्यो में वह चौथे स्थान पर थे लेकिन पेरिस में कमाल कर दिया। हरियाणा के किसान परिवार के तीरंदाज हरविंदर सिंह ने पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन स्पर्धा में देश को स्वर्ण पदक दिलाया है। वहीं एफ-51 स्पर्धा में धरमवीर ने सोना पर कब्जा किया। धरमवीर के साथी प्रणव सूरमा ने रजत पदक अपने नाम किया। टोक्यो पैरालंपिक के कांस्य विजेता हरविंदर ने सेमी फाइनल में ईरान के मोहम्मद रेजा को 7-3 से हराया। इस तरह वह फाइनल में पहुंचने वाले पहले तीरंदाज बने।

वन भूमि को बेजा कब्जा से मुक्त कराने कार्रवाई जारी

वन विभाग की उड़नदस्ता टीमों ने 23 के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर राज्य में वन भूमि से बेजा कब्जा खाली कराने तथा वन्य अपराध की रोकथाम के लिए वन विभाग की उड़नदस्ता टीमों के साथ-साथ विभागीय अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई कर रहे है।

जगदलपुर के अंतर्गत वन परिक्षेत्र भानपुरी में वन भूमि में बेजा कब्जा कर खेती करने के मामले में 23 लोगों के विरूद्ध वन अपराध का मामला दर्ज करने के साथ ही 26 एकड़ 29 डिसमिल वन भूमि में विभिन्न प्रकार की खड़ी फसलों सहित चैनलिंक, फेंसिंग खुटा, बारवेड वायर आदि जब्त किया गया है। उड़नदस्ता टीम द्वारा यह कार्रवाई भानपुरी परिक्षेत्र में वन भूमि पर बेजा खेती किए जाने की शिकायत मिलने पर जगदलपुर वन वृत्त के मुख्य वन संरक्षक श्री आर.सी. दुग्गा एवं वनमण्डलाधिकारी बस्तर श्री उत्तम गुप्ता के मार्गदर्शन में उड़नदस्ता टीमों ने दबिश दी और वन भूमि पर बेजा खेती करने का मामला सामने आने पर 23 लोगों के विरूद्ध

वन अपराध का मामला कायम कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदलपुर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की कार्रवाई की है।

राज्य स्तरीय उड़न दस्ता टीम ने भानपुरी वन परिक्षेत्र के चपका कक्ष में तीन व्यक्तियों द्वारा 1.81 एकड़ भूमि पर बेजा कब्जा कर मिर्ची एवं धान की खेती किए जाने का मामला पकड़ में आने पर फसल की जब्ती के साथ ही विकास देवांगन पिता अनिल देवांगन, राजू पिता सोमारू, तुलसी पिता मीठू के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया है। उड़नदस्ता टीम ने यहां से 8 बंडल चैनलिंक एवं 73 नग बांस का फेंसिंग खुंटा भी जब्त किया है।

वृत्त स्तरीय उड़न दस्ता टीम जगदलपुर ने ग्राम मुरकुची में 20 अतिक्रमणकारी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये 24.47 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण कर मक्का और उड़द की खड़ी करने वाले 20 लोगों के विरूद्ध वन अपराध का मामला दर्ज करने के साथ ही उनके पास से 10 बंडल फेंसिंग तार एवं 300 नग फेंसिंग खूंटा जब्त किया। वन भूमि पर बेजा कब्जा कर खेती करने के मामले में जिनके विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया हैं, उनमें ग्राम मुरूकुची निवासी डमरू, फूलसिंग एवं पांच अन्य, सुरेश एवं तीन अन्य, केलूराम एवं पांच अन्य तथा रूपनाथ एवं तीन अन्य व्यक्ति शामिल है।

कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री बिट्टू और विधायक गायकवाड का पुतला दहन किया

रायपुर/18 सितंबर 2024। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू एवं शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ के अमर्यादित बयान के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश

के सभी जिला मुख्यालय में दोनों नेताओं का पुतला दहन कर विरोध जताया और दोनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन से लेकर सड़क तक मोदी सरकार की तानाशाही मनमानी गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी के विरोध के बाद मोदी सरकार को 100 दिन में कई बार यू टर्न लेना पड़ा है और बीजेपी मोदी सरकार की संविधान विरोधी मनसा पर रोक लगा है इससे बौखलाई भाजपा के नेता और उनके गठबंधन शिवसेना के विधायक लगातार राहुल गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। भाजपा और उनके गठबंधन के नेताओं के इस हरकत को मोदी सरकार का संरक्षण है। भाजपा नेता ने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दिया है शिवसेना के विधायक ने उनके जीभ काटने की धमकी दी है। भाजपा का नेता हताशा में है राहुल गांधी को देश में मिल रहे जनसमर्थन से बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज उठाते रहेगी हम डरने वाले नहीं है भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश कर रही है कांग्रेस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि भाजपा और शिवसेना अपने दोनों नेताओं को पार्टी से तत्काल हटाए और उन पर कड़ी कानूनी कार्यवाही करें। प्रदेश के रायपुर शहर, रायपुर ग्रामीण, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण, भिलाई, बेमेतरा, राजनांदगांव शहर, राजनांदगांव ग्रामीण, कवर्धा, जगदलपुर शहर, बस्तर ग्रामीण, सुकमा, नारायणपुर, कोण्डगांव, बीजापुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर शहर, बिलासपुर ग्रामीण, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मुंगेली, कोरबा शहर, कोरबा ग्रामीण, जांजगीर चांपा, रायगढ़ शहर, रायगढ़ ग्रामीण, जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया सभी जिलों में मौन धरना प्रदर्शन हुआ।

कबीरधाम में खेली जा रही खून की होलीः डॉ. महंत

साहू समाज के युवाओं की हत्या से, समाज में आक्रोश- डॉ. महंत

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत बदतर होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार से कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है। गृह विभाग संहालने वाले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के गृह जिले कबीरधाम की हालात यह है कि वहां खुले आम खून की होली खेली जा रही है। अपराधियों को संरक्षण के चलते पुलिस पर भारी दबाव है, तथा आम लोगों में दहशत का माहौल है।

आज ही रेंगाखार थाने में गिरफ्तार 27 साल के युवा प्रशांत साहू की मौत, थाने में अत्यधिक मारपीट एवं प्रताड़ना के वजह से हुई है, इस घटना में रेंगाखार थानेदार एवं शामिल अन्य सिपाहियों पर हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार एवं तत्काल निलंबित किया जाए। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही अपराधियों के हौसले बुलंद हो गये है। सरकार के संरक्षण के चलते प्रदेश भर में जघन्य अपराध हो रहे हैं। कबीरधाम जिले के लोहारीडीह में हुई वारदात छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति की कहानी कह रही है। रेंगाखार क्षेत्र के ग्राम लोहारीडीह के युवक शिवप्रसाद साहू की संदिग्ध मौत से ग्रामवासियों में जो आक्रोश पनपा उसके लिए कबीरधाम जिले का पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। होनहार युवक शिवप्रसाद साहू के परिवार को भाजपा से जुड़े लोग परेशान कर रहे थे लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। कबीरधाम जिला पुलिस प्रशासन प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा से पूछे बगैर साधारण मामले में एफआईआर तक नहीं करता है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि ग्राम लोहारीडीह के युवक शिवप्रसाद साहू जो कि साहू समाज के मंडल अध्यक्ष थे की लाश जंगल में झाड़ में लटकते मिलना प्रथम दृष्टया हत्या का मामला होना स्पष्ट होता है। यह जंगल म.प्र. के बालाघाट जिले में है। कबीरधाम जिला पुलिस शिवप्रसाद साहू की मौत को आत्महत्या बताने में लगी है। चूंकि शिवप्रसाद साहू की फरियाद पर पुलिस ध्यान ही नहीं दे रही थी इसलिए उनकी मौत से ग्रामवासियों में छाया दुख आक्रोश बनकर फूट पड़ा।

बाबू भैया की कलम से

दक्षिण में प्रभावशाली कौन बृजमोहन या संगठन?

रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा का भले ही कहीं अतापता ना हो लेकिन सभी दलों की तैयारियां इतनी तेज हैं कि देखते ही बनता है। सालों साल एक ही हाथों में खेलती यह महत्वपूर्ण सीट अब तक भाजपा के दिग्गज व दबंग सदैव चर्चा में रहने वाले चर्चित नेता बृजमोहन अग्रवाल को अपना नेता चुनती आई है। इस बार मामला कुछ और हो गया है अब वे प्रदेश की राजनीति से बाहर नई दिल्ली की राजनीति में देश के सितारे बनने की राह पर हैं। रायपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं। तब प्रदेश की विधान सभा में उनकी दबंग आवाज से सदन चकित रहता था। अब उनकी आवाज छत्तीसगढ़ की समस्याओं की आवाज बन कर देश की संसद में गूंजती है। उनके सांसद चुने जाने से राजनीति के प्रादेशिक राजनीति के खिलाड़ी शायद यह मानने लगे थे कि अब प्रदेश में उनकी आवाज की गूंज सुनने को नहीं मिलेगी, देखा यह जा रहा है कि आज भी वे हर जगह, हर मामले में सक्रिय दिखाई देते हैं। हर कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी आज भी उन्हें चर्चा में रखती है। अखबार का कोई पन्ना नहीं होगा जहां रायपुर के किसी कार्यक्रम की तस्वीर प्रकाशित हो और प्रमुखता से उनका चेहरा ना दिखे। जनता के बीच अपनी मौजूदगी बनाए रखने की उनकी विशिष्ट कला व लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता में एक पैसे की भी कमी नहीं देखी जा रही है। उनके लोगों की अपनी परम्परागत टीम उन्हें कहीं भी चर्चा में ले आने में कामयाब है। आज भी उद्घाटन,लोकार्पण,भूमि पूजन ,नियुक्ति का उनका क्रम थमा नहीं है। आये दिन ऐसे कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति से वे प्रदेश के नेताओं को मात देते दिखाई दे जाते हैं। शायद ही आसपास के किसी संसदीय क्षेत्र के सांसद को इतना सक्रिय देखा जाता होगा। जनसेवा के लिए तत्पर दिखाई देने में उनका सानी नहीं है। प्रदेश में सीमेंट के दाम 50 रुपये बढे, तो उन्होंने तत्काल इसका खुला विरोध कर अपनी ही पार्टी को परेशानी में डालने में कोई गुरेज नहीं की। बयान दिया कि इससे सरकार व पार्टी की छवि धूमिल होगी। लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी। विपक्षी दलों को हथियार मिल गया विपक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री टैक्स लगाया गया है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह कि बृजमोहन अग्रवाल का वजन आज भी उतना ही कायम है जितना हुआ करता था। इसलिए रायपुर दक्षिण सीट पर उनके सलाह बिना कोई प्रत्याशी घोषित हो जाएगा ऐसा लगता तो नहीं। दोनों प्रमुख दलों में कवायद जारी है। कांग्रेस मान कर चल रही है कि बृजमोहन नहीं हैं तो यह सीट अब हमारी है। यह किन्हीं मायनों में सच भी है कि बृजमोहन की अपनी व्यक्तिगत छवि भी सबसे बडा कारण था कि वे दक्षिण विधानसभा के गढ़ के अजेय योद्धा बने रहे। बड़े बड़े कांग्रेसी योद्धाओं को यहां उन्होंने धूल चटा दी वे हमेशा क्रम से बढ़ते विजयी वोटों में इजाफा करतेव रहे। अब बृजमोहन का अभाव नये समीकरण तय करेगा। उनकी मैदान में अनुपस्थिति से इस सीट पर कांग्रेस टिकट के लिए दावेदारों की सूची लंबी हो चुकी है। प्रत्येक कांग्रेसी कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि अगर टिकट मिल जाए तो जीत पक्की है। उसी तरह भाजपा कार्यकर्ता इस सीट को अपनी परम्परागत विजयी सीट मान कर दावेदारी का आवेदन कर रहे हैं। उनमें भी भीड़ काफी है। भाजपा की टिकट या कांग्रेस की टिकट किसको मिलेगी ,अभी यह कहना तो सिर्फ अनुमान ही लगाना माना जाएगा। यह तय है कि बृजमोहन की लोकप्रियता के बरकरार रहने के मायने साफ हैं कि भाजपा संगठन उनकी मंशा के विरुद्ध जाकर कुछ करे तो जीत पर शंका के बादल घिरेंगें, इसकी संभावना ज्यादा बताई जा रही है। प्रत्याशी अगर बृजमोहन की पसंद का होगा तो तो जीत की सम्भावना पक्की मानी जाएगी। मैनेजमेंट के माहिर खिलाड़ी बृजमोहन हर हाल में जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगें। कहा जा सकता है कि भाजपा की मजबूरी है कि वो प्रत्याशी चयन में बृजमोहन अग्रवाल को पूरा महत्व दे। इधर कांग्रेस में यह कवायद चल रही है कि प्रत्याशी ऐसा हो कि हर हाल में यह सीट कांग्रेस की झोली में आये यह पक्का हो। सब दिग्गज यह मान रहे हैं कि अगर दक्षिण की यह विधान सभा सीट कांग्रेस जीत जाए तो कांग्रेस के लिए यह भविष्य में राजनीतिक संजीवनी साबित होगी। हार से हताश निराश पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा। सारे कांग्रेसी छत्रप इस भावी संभावना को समझ रहे हैं। अन्य मामलों में भले ही कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में मतभेद हों पर इस मामले में किसी में मनभेद होगा इसकी संभावना नहीं लगती। भाजपा व कांग्रेस उप चुनाव की घोषणा के पहले ही सारी तैयारियां कर लेना चाह रही हैं। चुनाव की घोषणा हो और प्रत्याशी का नाम तत्काल सामने आ जाए। प्रारम्भिक तैयारी से यही लगता है। देखना है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता एक मत से किसी का नाम तय कर पाते हैं या नहीं। भाजपा बृजमोहन अग्रवाल की मंशा के अनुरूप टिकट देती है या अपनी चौंकाने वाली पद्दति अपना कर किसी अप्रत्याशित नाम को सामने लाने का रिस्क उठाती है। जीत-हार इसी पर तय होगी।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

पुलिस पिटाई से कवर्धा में प्रशांत साहू की मौत हुई - कांग्रेस

रायपुर। कवर्धा जिले के लोहारीडीह मामले में जेल में बंद प्रशांत साहू की मौत हो गयी है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रशांत के साथ पुलिस ने बर्बरतापूर्वक पिटाई किया था उसे जेल भेजने के पहले ईलाज के लिये अस्पताल भी ले जाया गया था। मृतक के परिजनों का भी आरोप है पुलिस ने उसके साथ मारपीट किया था जिसके कारण उसकी मौत हुई थी। पोस्टमार्टम में भी चोट के निशान मिले है। कवर्धा सहित पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार की पुलिस बर्बर और तानाशाह बनी हुई है। कवर्धा में पुलिस की लापरवाही के कारण इतनी वीभत्स घटना हुई, एक व्यक्ति की हत्या हो गयी। पुलिस ने कार्यवाही नहीं किया। इस घटना के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। इस घटना के बाद पूरे गांव को आरोपी बनाया गया है। पुलिस अपनी खीझ गांव वालों पर निकाल रही, अमानवीय यातना दे रही थी। अंततः पुलिस की पिटाई से एक व्यक्ति की मौत हो गयी। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रशांत साहू के मौत की निष्पक्ष न्यायिक जांच कराई जानी चाहिये तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवही होनी चाहिये। प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है.

कांग्रेस के दबाव में सीमेंट के बढ़े हुए दाम कम हुए

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के आंदोलन धरना प्रदर्शन और दबाव के चलते ही सीमेंट के बढ़े हुये दाम में कमी करने को उद्योगपति मजबूर हुए हैं और सरकार दबाव में आयी है। भाजपा की सरकार तो उद्योगपतियों के सामने घुटना टेक दी थी। सीमेंट निर्माता ने कम्पनियों ने सिंडिकेट बनाकर सरकार को ठेंगा दिखाते हुए सीमेंट की बोरी में 50रु तक की वृद्धि कर दिये थे और सरकार में बैठे लोग मौन थे। इस बढ़ोतरी में सरकार की हिस्सेदारी थी। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ के उद्योगों में उत्पादन होने वाला सीमेंट छत्तीसगढ़ के बाहर के राज्यों में 20रु से 25 रु कम था जबकि छत्तीसगढ़ में 50 रु महंगा था। जबकि सीमेंट बनाने रॉ मटेरियल, बिजली, मैन पावर छत्तीसगढ़ में सस्ते दरों पर उपलब्ध है। राज्य की भाजपा सरकार चंद पूंजीपतियों की हाथों की कठपुतली है इन्हें गरीबों की चिंता नहीं थी बल्कि पूंजीपतियों से वसूली करने में सरकार खुद संलग्न थी। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद गरीबों के मकान बनाने के सपने को कुचल दिया गया है। सीमेंट के दाम में 50 रु की वृद्धि कर दी गई थी रेत के दाम 7000 रु प्रति ट्रक से बढ़कर 18000रु ट्रक हो गया है.

शहर में सरकारी और नजूल भूमि की होगी जांच- कलेक्टर

बिलासपुर। कलेक्टर अवनीश शरण ने बिलासपुर शहरी क्षेत्र में स्थित शासकीय एवं नजूल भूमि की जांच के लिए विशेष टीम गठित की है। एसडीएम बिलासपुर जांच टीम का नेतृत्व करेंगे। उनकी अध्यक्षता में गठित टीम में अलग-अलग क्षेत्रों के लिए 9 दल बनाये गये है। ये टीमें विस्तृत रूप से भू-अभिलेख की जांच कर 15 अक्टूबर तक रिपोर्ट देगी। मुख्य रूप से शासकीय भूमि एवं नजूल भूमि का मिशल बंदोबस्त एवं अधिकार अभिलेख से भौतिक सत्यापन करेगी। इस आधार पर वर्तमान अभिलेख की स्थिति एवं भूमि स्वामी दर्ज होने का कारण सहित विवरण देना होगा। जांच टीम अपने-अपने क्षेत्र में सर्वे एवं भौतिक सत्यापन का कार्य करेगी। जानकारी के मुताबिक कलेक्टर द्वारा गठित प्रत्येक टीम में पांच सदस्य होंगे। टीम का नेतृत्व संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी करेंगे। संबंधित क्षेत्र के नगर निगम के जोन अफसर एवं राजस्व निरीक्षक, राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक एवं हलका पटवारी इसके सदस्य होंगे। इनमें पहली टीम का नेतृत्व नजूल अधिकारी एसएस दुबे, दूसरी टीम में तहसीलदार अतुल वैष्णव, तीसरे टीम में अतिरिक्त तहसीलदार मुकेश देवांगन, चौथे टीम में अतिरिक्त तहसीलदार गरिमा ठाकुर, पांचवे टीम में अतिरिक्त तहसीलदार सिद्धी गबेल, छठें टीम में नायब तहसीलदार नेहा विश्वकर्मा, सातवें टीम में नायब तहसीलदार राहुल शर्मा, आठवें टीम में तहसीलदार संकरी अश्विनी कंवर और नवें टीम में नायब तहसीलदार रूचिका अग्रवाल नेतृत्व करेंगी।

आज शाम 4 बजे से होटल-बार समेत सभी शराब दुकानें रहेगी बंद

रायपुर। राजधानी रायपुर में कल यानि गुरुवार 19 सितंबर को गणेश झांकी निकाली जाएगी। इसके मद्देनजर जिला कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने रायपुर नगर निगम और बीरगांव नगर निगम क्षेत्र के सभी देशी और विदेशी शराब की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेंट-बार, होटल-बार, क्लब, और अन्य संबंधित स्थानों को कल शाम 4 बजे से बंद रखने का आदेश जारी किया है। बता दें कि यह आदेश छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 (1) के तहत जारी किया गया है। कलेक्टर ने इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की बात की है, ताकि गणेश विसर्जन का आयोजन शांति और व्यवस्था के साथ किया जा सके।

पीएम आवास योजना की राशि के लिए नपा के चक्कर लगा रहे हितग्राही

तखतपुर. प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही आवास की राशि के लिए नगर पालिका तखतपुर के लगातार चक्कर काट रहे. नगर पालिका में पिछले एक महीने से ज्यादा समय से प्रधानमंत्री आवास योजना के भुगतान के लिए करोड़ों रुपए रखा हुआ है, फिर भी हितग्राहियों को भुगतान नहीं हो पा रहा है. नए सीएमओ आने से हितग्राहियों में राशि जल्द मिलने की आस जगी है. यह पूरा मामला बिलासपुर जिले के तखतपुर नगर पालिका का है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को राशि भुगतान नहीं होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. राशि नहीं डलने से मकान अधूरे पड़े हैं. कई झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं. कई हितग्राही कर्ज लेकर मकान बनाकर कर्जे के बोझ तले दबे हुए हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने नगर पालिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राशि भुगतान करने के एवज में जनप्रतिनिधि और नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा पैसों का डिमांड किया जाता है. जब उनको पैसे नहीं देते हैं तो किस्त भुगतान नहीं होता है. इससे यह स्पष्ट होता है कि राशि भुगतान करने में खेल चल रहा है. गरीब तपके के लोग राशि भुगतान के लिए मुंह ताक रहे हैं और अधूरे बने घरों में रहने और जीवन यापन करने मजबूर हैं. इस मामले में नगर पालिका के आवास शाखा के प्रभारी ने बताया कि पूर्व में पदस्थ सीईओ के छुट्टी में चले जाने और फिर सीएमओ का तबादला हो जाने से यह समस्या उत्पन्न हुई है.

प्रधानमंत्री आवास दिलाने वाले बिचौलियों के संपर्क करने पर करें शिकायत- कलेक्टर

जिन लोगों के नाम सर्वे सूची में नहीं, उन पात्र हितग्राहियों के जोड़े जाएंगे नामः साहू

रायपुर। जिले के आज अभनपुर विकासखण्ड के ग्राम केन्द्री में जनसमस्या शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें सरस्वती सायकिल योजना के तहत स्कूली छात्राओं को सायकिल का वितरण किया गया। शिविर में 360 आवेदन प्राप्त किए गए जिनमें से 306 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। विधायक इन्द्र कुमार साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि आम जनता की समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो और उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ भी मिले। इसलिए ऐसे जनसमस्या निवारण

शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा श्रम विभाग की महत्वाकांक्षी योजनाओं का अवश्य लाभ लें। सभी पात्रता रखने वाले हितग्राही अपना श्रम कार्ड बनवाएं एवं नवीनीकरण भी करवाएं। श्री साहू ने कहा कि 17 सितम्बर को आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त हितग्राहियों के खाते में अंतरित की। विधायक श्री साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप जिन हितग्राहियों का नाम आवास प्लस और सर्वे सूची में शामिल नहीं है उनका नाम सर्वे कराने के पश्चात शामिल कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह योजना गरीबों के लिए एक बड़ा उपहार है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। गांव-गांव में जिन लोगों के नाम सर्वे सूची में नहीं आए हैं उनके नाम भी अब सूची में जोड़े जाएंगे। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि जिले में होने वाले ऐसे जनसमस्या शिविर में आम जनता अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखें, उनका समाधान जल्द से जल्द करने का प्रयास किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जनसमस्या निवारण कॉल सेंटर शुरू की गई है, इसमें भी आम जनता अपनी समस्याएं बता सकते हैं। डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि पीएम आवास योजना का पात्रता अनुसार सभी हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए यदि कोई भी बिचौलिया हितग्राहियों से संपर्क करता है, तो उसकी शिकायत प्रशासन के समक्ष कीजिए उस पर कड़ी से कड़ी से कार्रवाई की जाएगी। शिविर में हितग्राहियों को हित मूलक वस्तुओं का वितरण भी किया गया।

वन नेशन वन इलेक्शन भाजपा का जुमला

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी का जुमला बन गया है लोकसभा चुनाव के पहले से वन नेशन वन इलेक्शन करने का दावा इनके द्वारा किया जा रहा था लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है आज फिर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं भाजपा को दोनों राज्यों में करारी हार के संकेत मिल गए हैं जनता भाजपा के झांसा और बहकावे में नहीं आ रही है चारों तरफ भाजपा के खिलाफ आक्रोश दिख रहा है। तब भाजपा वन नेशन वन इलेक्शन का राग अलाप कर

जनता को मूल मुद्दों से भटकाने का षड्यंत्र कर रही है वन नेशन वन इलेक्शन भारत के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है इसे जनता स्वीकार नहीं करेगी। प्रधानमंत्री मोदी में साहस है कि वे इस्तीफा देकर एक साथ फिर से चुनाव करायेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा केंद्र में भाजपा की सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के रहमो करम पर चल रही है। 100 दिन के सरकार में जिस प्रकार से विपक्ष ने मजबूती के साथ मोदी सरकार को जन विरोधी नीतियों को और बिलों को वापस करने मजबूर कर दिया है भाजपा के गठबंधन दल के लोग भी मोदी सरकार के कई नीतियों का खुलकर विरोध कर चुके हैं ऐसे में भाजपा को महसूस हो गया है कि मोदी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। और देश में मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात करके हरियाणा और जम्मू कश्मीर के मतदाताओं को भ्रमित करने की चाल भाजपा चल रही है भाजपा कुछ भी कर रहे इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन संभव ही नहीं है और मोदी सरकार यदि मध्यवर्ती चुनाव में जाएगी तो भाजपा को 200 सीट भी नहीं मिलेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि देश की जनता भाजपा मोदी के झूठ और जुमले को समझ चुकी है लोकसभा चुनाव के पहले महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का बिल पास किया गया था.

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.